हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 जनवरी, 1976

खण्ड 1, अंक 5

अधिकृत विंवरण

विषय–सूची

शुक्रवार, 16 जनवरी, 1970

पृष्ठ संख्या

तारांकितप्रश्न एवं उतर (5)1

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (5)

वर्ष 1976– 77 का बजट पेश करना (5)30

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 16 जनवरी, 1976

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1 चण्डीगढ में 9. 30 बजे प्रातः हुई ।

अध्यक्ष

(चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उतर

Mr. Speaker : Question Hour.

तारांकित प्रश्न संख्या 1406

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी राम लाल वधवा, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1434

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी दल सिंह, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1454

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी देवी लाल, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Amount Earmarked for the Social Welfare Schemes

***1480. Chaudhri Shiv Ram Verma :** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state—

(a) the amount earmarked for the years 1975-76 and 1976-77, separately, for the different Social Welfare Schemes together with the names thereof ; and

(b) whether the amount had been allocated separately for each district ; if so, the amount so allocated ?

Excise and Taxation Minister (Shri Shyam Chand) :

(a) A statement showing the names of the different Social Welfare Schemes together with the amounts earmarked for the year 1975-76 separately is laid on the Table of the House. Similar information for the year 1976-77 would be available only after the budget for the year 1976-77 is passed by the Haryana Vidhan Sabha.

(b) No.

STATEMENT

Rs. in Lakh

Sr. No.	Name of the Scheme	Revised Budget grant for the year 1975-76

		Non-plan	plan	Total
1	Training Centre for the Adult Blind, Sonepat	1.85	-	1.85
2	Production Unit in Trg. Centre for the Adult Blind Sonepat	0.06	-	0.06
3	Govt. Institute for the Blind, Panipat	2.29	-	2.29
4	Scholarships to Physically Handicapped	0.33	0.25	0. 58
5	Saket Council, Chandimandir	1.16	-	1.16
6	Braille Library Panipat	0.13	-	0.13
7	Home for Destitute Women & Widows (Karnal, Rohtak and Faridabad)	2.26	0.60	2.86
8	Family and Child Welfare Proiects (Nilokheri, Sohna, Karnal, Pundri & Fatehabad)	3.60	-	3.60
9	Foster Care Service	0.52	0.15	0.67
10	Children Village Chhachhrauli	-	0.20	0.20
11	Home for aged & Infirm	0.90	-	0.90
12	State After Care Home, Madhuban	1.09	-	1.09
13	State Orphange Madhuban	-	-	-

14	Setting up of Production Unit in State After Care Home, Madhuban	4.72		4.72
15	Anti-Beggary Programme (Certified Institution, Panipat)	0.80	0.14	0.94
16	Grant-in-Aid to Haryana State Social Welfare Advisory Board (for Headquarter Staff)	0.68	-	0.68
17	Grant-in-aid to Voluntary Welfare Organisation	3.76	1.50	5.26
18	Special School Madhuban	0.67	0.70	1.37
19_	Old Age Pension Scheme	18.94	-	18.94
20	Holiday Home Society	0.28	0.10	0.38
21	Crash Nutrition Programme (13 towns)	2.11	6.45	8.56
22	Integrated Child Development Services Scheme	3.25	—	3.25
23	Functional Literacy for the Adult Women	0.98	—	0.9$
24	Welfare of Destitute Children	—	1.16	1.16
25	Direction & Administration Programmes	1.84	0.06	1.90
26	Relief Organisation (Mahila Ashram Karnal, Infirmary Rohtak and Kasturba Sewa Sadan Faridabad)	15.90	—	15.90

Grand Total : 68.12 11.31 79.43

चौधरी शिव राम वर्मा : मन्त्री महोदय ने जो स्टेटमैंट दी है इसमें कई स्कीमें लिखी हैं जिनकी कुल राशि 79. 43 लाख है लेकिन इन सारी स्कीमों में कमजोर वर्गों को मकान बनाने के लिये सहायता देने का कोई जिक्र नहीं है, तो क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि गरीब लोगों को मकान बनाने के लिये सहायता दी जाएगी?

श्री श्याम चन्द : इन्होंने सोशल वैल्फेयर स्कीम के बारे में पूछा था बह मैंने बता दिया । जो अब यह पूछ रहे हैं वह हरिजन वैलफेयर डिपार्टमैंट के तहत आता है ।

चौधरी शिवराम वर्मा : मैंने कमजोर वर्ग के लिये पूछा था जिसमें सब लोग आ जाते हैं क्योंकि समाज की भलाई के काम में मकान बहुत जरूरी हैं?

श्री श्याम चन्द : जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि यह हरिजन वैल्फेयर विभाग के अन्दर आता है ये दोनों अलग–अलग डिपार्टमैंट हैं ।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे हाउसिंग बोर्ड की ओर से इकोनोमीकली वीकर सैकशंज के लिये मकान बना कर दिये जाते हैं जो कम

कीमत पर दिये जाते हैं और कीमत किश्तों में वसूल की जाती है । '

श्री के. एन. गुलाटी : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि सोशल वैलफेयर की जितनी स्कीमें हैं इनका प्रचार करने का क्या तरीका है?

श्री श्याम चन्द : साइकिल पर तो हम इश्तिहार बांट नहीं सकते (हंसी) लेकिन हमारा पब्लिक रिलेशज डिपार्टमैंट और हरिजन वैलफेयर डिपार्टमैंट हैं उनके कर्मचारी हुनका प्रचार करते हैं ।

श्री अमर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि वैलफेयर स्कीम के तहत 1975–78 में कितनी विडोज को सिलाई मशीनें दी गई?

श्री श्याम चन्द : जितनी विडोज अलीजिबल थीं उनको दी गई । वैसे मैं आपको बता दूं कि पहले हम उनको वजीफा देते हैं जो कि 25 रुपये है फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है । मेरा ख्याल है कि 60 ऐसी विडोज हैं जिनको अगले महीने मशीनें देंगे ।

चौधरी मेहर चन्द : क्या मन्त्री महोदय बताएगे कि सोशल वैल्फेयर की स्कीमों से जो असिसटैसं मिलती हैं उनके लिये क्या कोई जिलावार कमेटियां फार्म की हुई हैं?

श्री श्याम चन्द : डिस्ट्रिक्ट–वाइज कोई कमेटी नहीं होती । हमारे सैटंर्ज हैं और हमारी 26 स्कीमें हैं । हमारी सरकार ने जो पंफलैट पब्लिश करवाएं हैं उनमें सारी स्कीमें दी हुई हैं, अगर आप पंफलैट पढ़ें तो सारी स्कीमों का पता चल जाएगा ।

श्री हरि सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि सोशल वैलफेयर डिपार्टमैंट के तहत इस वक्त हरियाणा में कितनी स्कीमे हैं जिनके द्वारा वैलफेयर का काम किया जाता है?

श्री श्याम चन्द : मैंने अभी बताया था कि 26 स्कीमें हैं ।

चौधरी शिव राम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अपने सवाल में यह भी पूछा था कि जिलावार अलग अलग बताई जाएं कि जिलावार कितनी कितनी रकम दी गई?

श्री श्याम चन्द : डिस्ट्रक्टवाइज बताना पौसीबल नहीं है । ये जो स्कीमें हैं इनका व्योरा जवाब में दे रखा है ।

श्री के० एन० गुलाटी : हर मंगलवार और शनीचरवार को हजारों की तादाद में बैगर्ज बाजारों में घूमते रहते हैं, पानीपत में बैगर हाउसिज की बहुत कमी है इसका क्या कारण है?

श्री श्याम चन्द : इनको अगर कोई नजर आए तो बता दें उनको हम बैगर हाउस में भेज देंगे ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो ओल्ड– एक पैनशन 25 रुपये दी जाती है क्या उसको 50 रुपये करने या बढ़ाने का विचार है या 50 से कुछ कम?

श्री श्याम चन्द : कम करने का तो कोई इरादा नहीं है लेकिन इसको बढ़ाने के लिये हमने गवर्नमैंट आफ इंडिया को लिखा था लेकिन उन्होंने एग्री नहीं किया ।

श्रीमती चन्द्रावती : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि यह जो वैल्फेयर स्कीमें हैं इनमें एडमिनिस्टेरटिव काम पर कितना खर्च आता है और बाकी स्कीमों पर कितना खर्च आता है?

श्री श्याम चन्द : स्पीकर साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपैंडिचर सैपरेट नहीं पूछा

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि ये केन्द्र जो किसानों की सेवा के लिये खोले गए हैं उनका रेट मार्किट के रेट से कितना कम है?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : मार्किट से 5 और 10 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से भाडा कम है ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो ट्रैक्टर जमीदारों को भाडे पर दिये जाते हैं क्या वे 2–3 घंटे के लिये भी दिये जाते हैं?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : अगर आप चाहोगे तो जरूर भेज देंगे ।

श्री हरि सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इन केन्द्रों के घाटे में चलने का क्या कारण है जबकि ये 40 रुपये घंटा लेते हैं और प्राइवेट 30 और 28 रुपये घंटा लेते हैं?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : यह बात मैंबर साहब गलत कह रहे हैं । प्राइवेट वाले 45 और 50 रुपये घंटा लेते हैं । हमें घाटा इसलिये है कि हम आप लोगों की सेवा करते हैं और सेवा करने के लिये घाटा खाना ही पड़ता है ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि निगम ने जो प्राइवेट लोगों को सैटंर्ज दिये हैं और दूसरे जो आपने खोले हैं क्या उनका रेट एक जैसा है या फर्क है?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिये ।

चौधरी शिव राम वर्मा : मुख्य. मंत्री जी ने फरमाया है कि ये केन्द्र सेवा करने के लिये हैं नफा कमाने के लिये नहीं हैं । क्या यह घाटा सेवा की वजह से हुआ है या गोल माल की वजह से हुआ है?

चौधरी सुरजीत सिंह : मानय सेवा की वजह से हुआ है ।

कृषि मन्त्री (कर्नल महा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह सैटंर्ज भारत सरकार और हरियाणा सरकार दोनों ने मिल कर हरियाणा में मकेनाइजड फारमिंग को फैलाने के लिये खोले थे । जिस वक्त ये खोले गये थे उस वक्त हरियाणा में 6570 ट्रैक्टर्ज थे लेकिन इन सैटंर्क के खोलने के बाद ये इतने पापुलराइज हुये कि 1974–75 में इनकी तादाद 23,540 हो गई । तो आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि इन सैटंर्ज के खोलने से कितना फायदा हुआ है ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : ये केन्द्र जो खोले गये हैं इन में ऐसा होता है कि किसान से तो फीस के पैसे पहले जमा करवा लेते हैं लेकिन जो टाइम देते हैं उस टाइम पर ट्रैक्टर्ज पहुंचते नहीं हैं, जिससे किसानों को बहुत तकलीफ होती है । क्या वजीर साहब बतायेंगे कि वह ऐसा इन्तजाम करेंगे कि जो टाइम किसान को ट्रैक्टर पहुंचने का दिया जाये उसी टाइम पर ट्रैक्टर पहुंच जाये?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : कोशिश यही होती है कि टाइम पर जायें लेकिन मशीनरी की बात है जो कई दफा खराब हो जाती है इसलिये कुछ देरी हो जाती है । यह ठीक है कि पैसे एडवांस लेते हैं लेकिन आधे पैसे ऐडवांस लेते हैं बाकी आधे पैसे बाद में लेते हैं ।

चौधरी अमीर चन्द कक्कड़ : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि शाहाबाद में इस सैटर की बहुत जरूरत है तो वहां पर कब तक खोलने की कृपा करेंगे?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : अगर खोलने की जरूरत हुई तो खोल देंगे ।

चौधरी मेहर चन्द : मैं यह जानना चाहता हूं कि 197 5–7 6 में कितने ऐसे किसानों को जिनके पास 10 एकड़ से कम कमीन थी ये ट्रैक्टर्ज दिये गये और कितने ऐसों को दिये गये जिनकी दस एकड़ से ज्यादा जमीन थीं?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : इस के लिये तो आप सैप्रेट नोटिस दें यह तो बहुत लम्बी चौड़ी बात है कि कितने दस एकड़ से ज्यादा और कितने दस एकड़ से कम जमीन वाले किसानों ने ये ट्रैक्टर लिये ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि प्राइवेट वालों का ट्रैक्टर का किराया कम है और निगम वालों का किराया ज्यादा है लेकिन फिर भी वे लौस में जा रहे हैं इसका क्या कारण है इसकी जांच करायेंगे?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : अगर ऐसी बात है तो जांच करवा लेंगे।

श्रीमती चन्द्रावती : क्या सरकार के पास रिकार्ड में है कि कितने किसानों ने हर सैंटर में ट्रैक्टर लेने के लिये दरखासतें दीं, कितनों को टाइम पर ट्रैक्टर नहीं मिले और कितनों को इन्कार किया गया?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : सब को दिये जिन्होंने ट्रैक्टर मांगे क्योंकि हमारे पास तो ट्रैक्टर खाली पड़े हैं ।

राव बंसी सिंह : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि जिला महेन्द्रगढ़ में किस–किस स्थान पर ये सैटर चल रहे हैं और कितने चल रहे हैं?

कर्नल महा सिंह : 23 सेटंर्ज में से दो जिला महेन्द्रगढ़ में रिवाडी और कुंड में हैं । 73 जो और खोले गये हैं उन में से चार महेन्द्रगढ़ में खोले गये हैं और वे अटेली, नारनौल, महेन्द्रगढ़ और जाटूसाना में हैं ।

श्री अमर सिंह : क्या वजीर साहब बतायेने भिवानी और हिसार जिलों में यह केन्द्र कहां कहां पर खोले हुए हें?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : मैं सभी जगहों के बारे में बता देता हूं कि क्हा कहां पर हैं और वे स्थान हैं, नीलोखेडी, करनाल, पानीपत रोहतक, भिवानी, जींद, हिसार, सिरसा, पलवल, गुड़गांव, जगाधरी, गोहाना, हांसी, लाडवा, पहेवा, अम्बाला, रिवाडी, फिरोजपुर झिरका, लाखन माजरा, झझर, कुंड, लोहारू और तोशाम ।

राव बंसी सिंह : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि महेन्द्रगढ़ में जिस एक स्थान पर यह केन्द्र चल रहा है वह किस स्थान पर है लोगों को तो उसका पता नहीं कि किस के पास वह सैंटर है और कौन उसे चला रहा है?

कर्नल महा सिंह : किस व्यक्ति के पास वह सैटर है इस के लिये नोटिस चाहिये । बाकी जो 73 सर्विस सैंटर्ज खोले गये हैं कारपोरेशन की मदद से ये प्राइवेट आदमियों ने खोले हैं और उन में से एक महेन्द्रगढ़ में खोला गया है ।

Drought Prone Areas

***1507. Rao Dalip Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether any scheme has been sanctioned for development of the drought-prone areas of districts Mohindergarh and Bhiwani ; and

(b) the details of the scheme and the time by which it would be implemented ?

State Minister for Agriculture and Revenue (Chaudhri Surjit Singh Mann):

(a) Yes, the scheme has been sanctioned.

(b) A scheme for the development of Drought Prone Areas of districts Mohindergarh and Bhiwani has been formulated at a total cost of Rs. 7.80 crores at a matching contribution between Government of India and State

Government. The total allocation of central assistance for different areas has been made in Rs. 2.5 crores for Mohindergarh district, Rs. 1.1 crore for Bhiwani district and Rs. 0.3 crore for Jhajjar Tehsil of Rohtak district. The scheme is to be implemented during the 5th five year plan. The total magnitude of programme in different sectors is as follows :--

Sr.	No. & Sector	Total cost (In lakhs)	Project	Credit
1.	Agriculture including Soil & Moisture conservation	250.41	167.08	82.33
2.	Irrigation	882.09	345.21	536.88
3.	Afforestation	60.00	60.00	-
4.	Cattle and Dairy Dev.	165.59	105.59	60.00
5.	Sheep and Wool Dev.	47.10	32.49	14.61
6.	District Agencies at Mohindergarh and Bhiwani	13.75	13.75	-
7.	Strengthening of Co-op. Agency	15.00	15.00	-
8.	Reserve	40.00	40.00	-
		1,473.94	780.12	693.82

राव दलीप सिंह : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि अब तक इस स्कीम पर कितना खर्च हुआ है और स्टेट गवर्नमैंट ने कितना इस में से खर्च किया है?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : 67 लाख रुपया खर्च कर चु के हैं इस वक्त और इस में से आधा स्टेट गवर्नमैंट ने खर्च किया है और आधा सैंट्रल गवर्नमैंट ने किया है ।

राव बंसी सिंह : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि इस स्कीम का हैड आपिस कहां पर है और इस स्कीम को चालू करते समय कौनसे प्रोजैक्ट स्टार्ट किये गये?

कृषि मन्त्री (कर्नल महा सिंह) : महेन्द्रगढ़ जिले का हैडक्वार्टर नारनौल है और भिवानी जिले का भिवानी में है ।

राव दलीप सिंह : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इस प्रोजैक्ट के लिए क्या कोई प्रोजैक्ट आफिसर नियुक्त किया गया है?

कर्नल महा सिंह : भिवानी में मुफाल का जो प्रोजैक्ट आफिसर है वही इस प्रोजैक्ट का काम करताहै और महेन्द्रगढ़ में एक आई0 ए0 एस0 आफिसर लगाना है जिसका मामला सरकार के विचाराधीन है ।

राव दलीप सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि अगले साल इस प्रोजैक्ट पर कितना रुपया खर्च करने का विचार है?

कर्नल महा सिंह : अगले साल 1 करोड 18 लाख रुपया खर्च करने का अनुमान है ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, महेन्द्रगढ़ और भिवानी में ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है क्योंकि वहां की हालत बड़ी बदतर है । सरकार ने महेन्द्रगढ़ में मुफाल का पैसा बिल्कुल नहीं रखा और जो खर्च हो रहा है वह ठीक तरह से खर्च नहीं हो रहा । क्या सरकार सैन्ट्रल गवर्नमैंट से परसुएशन करके इस जिले में ज्यादा पैसा खर्च करने की कोशिश करेगी?

कर्नल महा सिंह : सरकार सैन्ट्रल गवर्नमैंट से दरख्वास्त कर रही है कि भिवानी के अन्दर मुफाल को रखा जाए क्योंकि डी० पी० ए० पी० की बजाए मुफाल से लोगों को ज्यादा फायदा होगा, लेकिन इसका फैसला भारत सरकार से होना है ।

राव दलीप सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि ड्राट परोन एरियाज के लिए जो 7. 80 करोड़ रुपया रखा गया है, यह कब तक इस्तेमाल किया जाएगा?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : फाइव इयर प्लान के अन्दर ।

तारांकित प्रश्न सं० 1524

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी चाँद राम, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Construction of Spurs

***1531. Lala Rulya Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to save village Mundigarhi and Lalupura in Tehsil and District Karnal from recurrence of floods in river Jamuna by constructing spurs at suitable places ; and

(b) if so, the time by which the said proposal is likely to be materialized ?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha) :

(a) Yes, sir.

(b) A period of about six months will be required for construction, if Third Thermal Plant

लाला रुलिया राम : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने मुंडीगढी और लालुपुरा गावों को फ्लड से बचाने के लिए सपर्ज बनाने की स्कीम मन्जूर की है, लेकिन अगर यह काम लेट हो गया तो लोगों को बड़ी मुश्किल होगी । जो रकम रखी जाती है वह जाया चली जाती है । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस काम को जल्दी शुरु किया जार ।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब! मुडीगढी पर 1972 में 79 हजार रुपया खर्च किया फलड आने से पहले,

और 1974 में 1 लाख 75 हजार रुपया खर्च किया है । इसी तरह लालुपुरा पर 1974 में 1 लाख 50 हजार रुपया और 1975 में 2 लाख 21 हजार रुपया खर्च किया है । आप देखें, इतना रुपया खर्च हो चुका है और अब दोनों गावों की सिंचाई की स्कीम बनाई हैं जिन पर 3 लाख 31 हजार रुपया लगेगा । यह रुपया लगने के बाद इन गावों की कोई दिक्कत नहीं रहेगी ।

लाला रुलिया राम : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जमुना पर जो छोटे–छोटे बांध हैं, उन के टूट जाने से फ्लड का पानी आ जाता है और बड़ा नुक्सान होता है, क्या सरकार इस नुक्सान को रोकने के लिए कार्यवाही करेगी?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : गवर्नमैंट इस बात को अच्छी तरह जानती है । फ्लड की वजह से जो नुक्सान होता है उसको नहीं होने देगी, इस बात के लिए जमना के साथ के एरिए के लिए जिस में फ्लड आते हैं, प्रपोजल बनी हुई है, उसके मुताबिक, पैसे का इन्तजाम कर के यह कोशिश की जाएगी कि किसी का नुक्सान न हो ।

श्री के ० एन० गुलाटी : फरीदाबाद में पांच छः जगहें ऐसी हैं जहां सपर्क बनाने जरूरी हैं, क्या सरकार इन सपर्ज को बनाएगी?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, पांच छः सपर्ज की बात नहीं है कई सपर्ज की बात है, सैकड़ों सपर्ज हैं,

हर एक के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, आप सैपरेट नोटिस दें, जबाब दे दिया जाएगा ।

श्री हरि सिंह : क्या मिनिस्टर साहब के नोटिस में है कि कई हजार एकड़ जमीन जमना के फ्लड से खुर्दबुर्द हो गई हैय अगर है तो इस फलड को रोकने के लिए कब तक काम चालू हो जाएगा ताकि लोग आयंदा ड़गने वाले बरसाती फ्लड से रिलीफ महसूस कर सकें?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : जो दो गांव लाला रुलिया राम ने कहे थे उनकी स्कीम और उसके नीचे 9 और गांवों की स्कीम फ्लड कंट्रोल बोर्ड से एप्रूव हो चुकी है, पैसा मिलने के बाद शुरू की जाएगी ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि फ्लड से जो नुक्सान लोगों को हो रहा है, क्या यह सरकार की वजह से हो रहा है या किसी और कारण से हो रहा है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : सरकार की वजह से कतई नुक्सान नहीं हुआ बल्कि सरकार की वजह से फायदा हुआ है ।

श्री बिहारी लाल बाल्मीकि : स्पीकर साहब, जमना से हर साल बाढ़ आती है और आस पास के गांवों में बहुत नुक्सान होता है । इसकी रोकथाम करने के लिए सरकार ने क्या इन्तजाम

किया है? सदवागढी, टप्पा बलोचपुर, माहोली इन गावों के किनारों पर पत्थर की ठोकरें लगाई जायें ।

मुख्य मन्नी (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, यमुना नदी अपना रास्ता बदलती रहती है और कई बार हरियाणा प्रदेश के अनेक गांवों को, और जमीन को बड़ा नुक्सान होता है । इसकी रोकथाम के लिए सरकार का डिपार्टमैंट पूरी तरह विजिलैट है, सतर्क है । यमुना के साथ जहां खादर का एरिया है, उस पर सरकार की पूरी नजर है । जिन जिन गांवों को खतरा पैदा हो सकता है, जिस जमीन को खतरा पैदा हो सकता है, उसकी रक्षा के लिये प्रबन्ध किया जाता है । प्रोटैक्शन के लिए हमारे फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने, गवर्नमैंट ने पूरी सकीमें बनाई हैं । जैसे पैसा उपलब्ध होता रहेगा हम उस इलाके को बचाने का पूरा इन्तजाम करेंगे ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि झज्जर तहसील में जहां फ्लड का पानी खड़ा है, उसको निकालने के लिए क्या कोई प्रबन्ध किया है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : जहां पानी खड़ा हुआ था वहां से पम्पों के जरिए पानी निकाल दिया गया है । अगर एक आध गांव रह गया हो तो मेम्बर साहब मेरे नोटिस में जाए ।

श्री हरि सिंह : स्पीकर साहब, हमने करनाल में बांध बांधने वाले अफसरों को कंटेक्ट किया तो उन्होंने फरमाया कि

रुपया समय पर मिलता नहीं, फ्लड आ जाते हैं और सारा पैसा जाया जाता है, जो काम शुरू होता हए वह कम्पलीट नहीं होता और सारा किया कराया काम फ्लड से बह जाता है । क्या मन्डी महोदय बताएंगे कि यह रुपया कौन सी डेट तक देंगे ताकि बांध समय पर बनाए जा सकें?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : कोशिश की जा रही है कि फ्लड से पहले पहले जो काम हाथ में लिए जाएं उन को जरूर मुकम्मल किया जाए ।

चौधरी शिव राम वर्मा : सरकार फ्लड से बचने के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन हरियाणा में छोटी छोटी लिंक डेरन्ज है, उनको कितनी देर में मुकम्मल किया जाएगा, उन से भी काफी रकबा पानी के नीचे आ जाता है और काफी नुक्सान होता है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : जो पुरानी ड्रेन्ज हैं उन पर साथ साथ काम चल रहा है और जिन पर काम शुरू है उन को बारिश शुरू होने से पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे । यह जनता के हित की सरकार है, जनता के हित के काम पहले करेंगे ।

लाला रुलिया राम : जो रुपया स्कीम के लिए दिया जाता है वह टाईम पर नहीं दिया जाता इसलिए काम नहीं हो पाता । इसलिए मेरी गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके इस काम को शुरू करवा दें ।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : मैं लाला रुलिया राम जी को यकीन दिलाता हूं कि इस दफा ऐसी बात नहीं होगी, बारिश शुरू होने से पहले, फ्लड आने से पहले जो काम हाथ में लेंगे, उसको मुकम्मल कर देंगे ।

श्री हरि सिंह : क्या मिनिस्टर साहब जमना के किनारे किनारे बने हुए हर बांध को खुद जाकर देखेंगे. ताकि उन को सारी सिचुएशन का पता चल जाए?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : मैंने बहुत देखे हैं, अगर इन का ख्याल है कि एक आध देखने से रह गया है तो मुझे छुट्टियों में ले जाएं' । मैं देख लूंगा ।

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब, सांपला के पास अब भी फ्लड का पानी खड़ा हुआ है, क्या मन्त्री महोदय उसको निकलवाने का इन्तजाम करेंगे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : हरियाणा के सात हजार गांव हैं, इन सब के बारे में मैं क्या कह सकता हूं ।

Third Thermal Plant

***1557. Shri K.N. Gulati :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is proposal under consideration of the Government to instal 3rd Thermal Plant at Faridabad, and

(b) if so, the time by which it will be installed together with the location thereof at Faridabad ?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha)

(a) Yes.

(b) Within a period of about forty months after the final approval of the Govt. of India is accorded to the project report pending for techno-economic approval.

श्री के0 एन0 गुलाटी : क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि मौजूदा थर्मल प्लान्ट्स जो 100 लाख क्युसिक फीट पानी अनप्लांड ढंग से देहाती इलाकों में फैंक देते हैं, उसे कब तक कंप्लैक्स ऐडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि काफी अर्से से सरकार से उस पानी की मांग कर रहा है, दे देंगे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, यह पानी का सवाल नहीं है, यह तो थर्मल प्लान्ट्स का सवाल है ।

श्री के० एन ० गुलाटी : पानी थर्मल प्लांटस का ही है ।

चौधरी मनफूल सिंह : क्या मंत्री महोदय फरमायेंगे कि इस प्लांट की टोटल कौस्ट कितनी होगी और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : इस प्लांट के ऊपर 17 करोड़ 67 लाख रुपये लगेंगे और जब गवर्नमैंट आपा इंडिया और प्लानिंग कमीशन, इसकी ऐप्रूवल दे देंगें, उसके चालीस महीने के अन्दर–अन्दर यह कम्पलीट हो जाएगा । इसकी कैपेसिटी 60 मैगावाट की होगी । इसके बनने से 80– 60 मैगावाट के तीन प्लांट्स वहां हो जाएंगे । एक पहले चरन रहा है ।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं भी थोड़ा सा निवेदन कर दूं । यह जो कौस्ट बतलाई अभी राज्य मंत्री जी ने 17 करोड़ 67 लाख रुपये की, यह वैसे काफी कम है । अगर आज कोई नया यूनिट 60 मैगावाट का हमने लगाना हो तो उसके ऊपर 35 करोड़ रुपये की लागत आती है । हमारे इस यूनिट में सिविल वर्क पहले हो चुका है इसलिए आधी कौस्ट पर हमारा यह यूनिट तैयार हो जाएगा ।

चौधरी मनफूल सिंह : जो सैकिंड थर्मल प्लांट है उसकी कैपेसिटी कितनी है और उस पर कौस्ट कितनी आई है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिह चट्ठा : स्पीकर साहब, कौस्ट का जहां तक सम्बन्ध है, यह सारे प्लांट्स की सांझी चलती है क्योंकि जमीन सबकी इकट्ठी होती है, चिमनी एक होती है स्वाह फैकने की जगह एक होती है, इनकी कालोनी की जगह इकट्ठी होती है । इनके अलावा और भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो सारे प्रोजैक्टस के लिए इकट्ठी होती हैं । इस लिए तीनों प्रोजैक्टस की

अलग अलग कौस्ट को बताना मुश्किल होता है । वैसे अब तक 35 करोड़ रुपये खर्च आ चुका है, थोड़ी सी रकम और लगेगी ।

श्री हरि सिंह : क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि फरीदाबाद में जिस जगह पर तीसरा प्लांट बनने जा रहा है वह जगह उसके लिए नाकाफी नहीं है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : फरीदाबाद में हमारे पास 147 एकड़ जगह है जिसमें 27 एकड़ रैजीडैन्स के लिए है, 20 एकडू थर्मल प्लांट के लिए है और एक सौ एकड़ एऐश फैकने के लिए है । जगह की हमें कोई दिक्कत नहीं है ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि पानीपत का थर्मल प्लांट कब तक कंप्लीट हो जाएगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : सवाल तो वैसे फरीदाबाद का है लेकिन मैं बता दूं कि पानीपत का थर्मल प्लांट 78–79 में आने वाला है ।

तारांकित प्रश्न सं० 1407

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी राम लाल वधवा, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्रश्न सं ० 1435

यह प्रश्न पूछ' नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी दल सिंह, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्रश्न सं ० 1455

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकिं माननीय सदस्य, चौधरी देवी लाल सदन में उप–स्थित नहीं थे ।

Harvest-Combines

***1493. Shri Om Parkash Garg :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the total number of Harvest-Combines procured so far by the Agro-Industries Corporation, Haryana ;

(b) the profit earned or loss incurred so far from the sale of Harvest-Combines ; and

(c) the number of said Harvest-Combines which are functioning properly and of those which are lying defective as at present, separately, and the dates from which these are lying defective 9

State Minister for Agriculture and Revenue (Chaudhri Surjit Singh Mann.):

(a) 68.

(b) Profit of Rs. 7.5304 lass tiff December, 1975.

(c) Out of 68 Harvest-Combines, 29 have been sold, 33 are functioning properly and 6 are lying defective from the dates given below :—

Number	Date
2	5-5-1972
1	4-5-1973
1	12-11-1973
1	20-4-1974
1	4-5-1974

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मंत्री महोदय फरमायेंगे कि एक हारवैस्ट कम्बाइन की क्या कीमत है?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : हरेक की अलग अलग कीमत है जो कि इस प्रकार है –

	Make & Model	Price
1.	John Deera-330	1,07,226
2.	Vicon	26,240
3.	Massey Ferguson	75,756
4.	SKPR---4	1,10,806
5.	John Deera-630	1,91,618
6.	John Deera-330	1,19,179
7.	G.D.R.	1,73,840

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : क्या मंत्री जी बतलाएंगे कि हारवैस्ट कम्बाइन्ज आने से देहात में फसल काटने वाली लेबर

बेकार नहीं हुई है? अगर हुई है तो क्या इन्हें बंद कराने की कृपा करेंगे?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : ऐसी कोई बात नहीं है । लेबर को काम अभी भी बहुत है, करने वाले चाहिए ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : मिनिस्टर साहब ने अभी बताया कि कुछ हारबैस्ट कम्बाइन्ज 72 में खराब हुए और कुछ 73 में खराब हुए । लेकिन अब तो 76 आ गया है । क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि उनकी मुरम्मत कराने का कोई प्रबन्ध किया गया है या नहीं? यदि न हीं किया गया है तो क्यों इतनी देरी की गई?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : बात यह है कि ये इम्पोर्टिड हैं । पार्ट? स मंगवाने के लिए इम्पोर्ट लाईसैन्स चाहिए था । इम्पोर्ट लाईसैन्स अभी आया है । पार्टस अब आ रहे हैं । दो के आ चुके हैं, चार के आने वाले हैं । जिनके पार्टस आ चुके हैं वे शीघ्र ही चालू हो जाएंगे और बाकी के पार्टस आने पर चालू हो जाएंगे ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : मंत्री महोदय ने बताया कि कुछ हारवैस्ट कम्बाइन्ज इम्पोर्टिड हैं । क्या वे बताएंगे कि बाकी के इंडिजिनियस हैं?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : पांच इंडिजिनियस हैं ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या बाकी के खराब होने का मुकाम है?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : कोई मुकाम नहीं ।

मलिक सतराम दास बतरा : क्या मंत्री महोदया बतलाने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में चौफ और फौडर का जब 25–30 रुपये क्विंटल का भाव है और हारवैस्ट–कम्बाइन्ज चौफ को खेत में ही डिसट्राय कर देता है । क्या यह जमीदार के लिए अनइकनौमिक नहीं है?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : हमारे यहां तो सरप्लस है ।

Mr. Speaker : Order please. It is not a supplementary question.

चौधरी अमीर चन्द कक्कड़ : मंत्री महोदय ने दो हारवैस्ट–कम्बाइन्ज 1972 में खराब बताए हैं । क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि उनकी डेट आफ परचेज क्या है?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : डेट आफ परचेज अलग अलग है । कुछ 1970– 71 में खरीदे हैं, कुछ 72 में खरीदे हैं, कुछ 73 में खरीदे हैं और कुछ 74 में भी खरीदे हैं ।

श्री हरि सिंह : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि ये जो हारवैस्ट–कम्बाइन्ज खराब पड़े हैं, ये कहीं खराब ही तो नहीं खरीदे गए थे?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : बिल्कुल हैन्ड न्यू खरीदे गए थे ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी जवाब देने की इतनी जल्दी न किया करे । पहले सवाल पूरा होने दिया करें ।

चौधरी सुरजीत सिंह मान : वे तकरीबन बैन्ड न्यू खरीदे हैं ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : मंत्री जी ने फरमाया है कि कुछ हारवैस्ट–कम्बाइन्ज सेल किए हैं । क्या वे फरमायेंगे कि वे कितने में सेल किए हैं और कितने में परचेज किए गए थे?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : यह तो टोटल करना पड़ेगा । प्राइसिज मैंने आपको बता दी हैं । बेचे 6,40,150 रुपये में हैं ।

कृषि मंत्री (कर्नल महा सिंह) : घाटे में नहीं बेचे गए ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो हारवैस्ट–कम्बाइन्ज खराब हैं वे कितने कितने दिन चले हैं और कितने दिन चलने के बाद खराब हुए हैं?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : ये 71– 72 से खराब हैं । ठीक करने की कोशिश की जा रही है । ठीक होने के बाद फिर चल जाएगें ।

कर्नल महा सिंह : स्पीकर साहब, इस जवाब को थोड़ा सा मैं कुरैक्ट करूंगा । ये हारवैस्ट–कम्बाइन्ज जो खराब हैं 70–71 में आए थे । कुछ दिन ये चले हैं । कुछ हारवैस्ट कम्बाइन्ज हमने पुराने सैकिन्ड हैन्ड भी खरीदे थे जो खराब हो गए । हम उनके पार्टस मंगवाने की कौशिश कर रहे रहे हैं । दो के पार्ट? स आ चुके हैं, चार के आने वाले हैं । जब पार्टस बाहर से मंगवाने होते हैंतो इम्पोर्ट लाईसैन्स लेना पड़ता है । इसमें इतनी फालिटीज पूरी करनी होती हैं जिसमें देरी लग जाती है ।

राव बंसी सिंह : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो सैकिंड हैन्ड हारवैस्ट–कम्बाइन्ज खरीदे गए थे वे यहां से खरीदे, गए हैं या बाहर से खरीदे गए हैं?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : बाहर से खरीदे गए हैं ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : मिनिस्टर साहब ने अभी बताया कि हारवैस्टर–कम्बाइन्ज 70– 71 में आए और 72– 73 में खराब हो गए । यह मशीनरी है । इसके स्पेयर पार्ट्स हमेशा अपने पास रखने चाहिए । क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि आयंदा के लिए और स्पेयर पार्टस मंगवाने के लिए अभी से कार्यवाही करेंगे?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : जरूर करेंगे ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि एक इम्पोर्टिड हारवैस्ट कम्बाइन जब 1,73,000 के करीब का पड़ता है तो 29 हारवैस्ट कम्बाइन्ज इन्होंने साढ़े छः लाख रुपये के क्यों बेचे?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : उनमें कुछ पुराने भी शामिल थे, इसलिए बेच दिए ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे किसी को फायदा पहुंचाने के लिए खरीदे थे?

चौधरी सुरजीत सिंह मानः वे तो बाहर से खरीदे थे

श्री ओम प्रकाश गर्ग : वे किस ने खरीदे थे और वे बाहर से किस को फायदा पहुंचाने के लिए खरीदे गये थे ।

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

श्री के० एन० गुलाटी : क्या आनरेबल मिनिस्टर चौधरी सुरजीत सिंह जी बतायेंगे कि वे नये मिनिस्टर बने हैं, इसलिए उनपर सप्लीमेंटरी सवालों की बुछाड हो रही है या कोई और कारण है?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : ये सब मेरे दोस्त हैं ।

चौधरी श्याम लाल : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि ये हारवैस्ट कम्बाइन केवल हरियाणा में इस्तेमाल होते हैं या दूसरी स्टेट्स में भी भेजे जाते है?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : हरियाणा में ही होते हैं ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : स्पीकर साहब, मती महोदय ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया । मैंने सप्लीमेंटरी किया था कि ये हारवैस्टर किस को फायदा पहुंचाने के लिए खरीदे गये और किस को फायदा पहुंचाने के लिए बेचे गयेय क्या इस बारे में जांच करायेंगे?

Mr. Speaker : Order please. It is not a supplementary question.

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए खरीदे गये हो और किसी विशेष व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए ही बेचे गये हो । यह बात बिल्कुल निराधार है । हारवैस्ट कम्बाइन इसलिए खरीदे गये थे कि जिस वक्त हरियाणा में बम्पर क्रोप होती है तो खासकर करनाल और कुरूक्षेत्र के एरिया में मैनुअल लेबर नहीं मिलती है । काफी मजदूरी आफर करने के बाद भी लेबर नहीं मिलती है । एक साल की बात तो मुझे याद है कि खड़ी फसलें कुड़ गयी लेकिन उसकी हारवैस्टर नहीं कर पाये । तो किसान के फायदा के लिए, स्टेट के फायदा

के लिए हारवैस्ट खरीदे गये । इनकी रिपेयर में इकोनौमिकली थोड़ा बहुत घाटा रहा हो लेकिन सारी स्टेट का इसमें हित है ।

District-wise Applications pending for Tubewell connections

***1508. Rao Dalip Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the district-wise total number of applications pending for tubewell connections in the State at present ;

(b) the total number of applications of persons who have deposited Rs. 2,500 in each case with the Haryana State Electricity Board pending for tubewell connections district-wise to date, and

(c) the total number of applications pending for tubewell connections who have purchased their own material to date ?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha) :

(a) The district wise information is not available as the boundaries of Board's circles are not co-terminus with the revenue boundaries of the districts. The circle-wise No. of pending applications for tubewell connection as on 30th November, 1975 is as under :—

Circle	No. of applications pending as on 30-11-75

1.	Chandigarh	2,046
2.	Karnal	4,565
3.	Delhi	4,377
4.	Faridabad	1,094
5.	Hissar	1,332
6.	Rohtak	3,565
	Total	16,979

(b) The circle-wise No. of pending applications who have deposited Rs. 2,500/—as on 30th November, 1975 is as under :—

	Circle	No. of persons whc have deposited Rs. 2,500/-
1.	Chandigarh	12
2.	Karnal	52
3.	Delhi	15
4.	Faridabad	--
5.	Hissar	81
6.	Rohtak	42

Total 202

(c) 13

राव दलीप सिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिन्होंने अढाई हजार रुपया जमा करवाया हुआ है और जिनको कुनैक्शन नहीं दिये गये वे 202 केसिज पैंडिंग हैं । क्या सरकार उनको कुनैक्शन देने में प्रायरिटी देगी?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : उनको हम प्रायरिटी देते हैं जिन्होंनें अढाई हजार रुपया जमा करवाया हुआ होता है लेकिन उनकी लाइनें बहुत लम्बी होती है । हमें बड़े ट्रांसफार्मर रखने के लिए इलैवन के ० वी० लाईन खींचनी पड़ती है । इस दिक्कत के होने के बाद भी हम उनको ज्यादा से ज्यादा कुनैक्शन देने का यत्न कर रहे हैं ।

राव दलीप सिंह : अढ़ाई हजार रुपया लेने के बाद भी आप यह कहते हैं कि लाइनें लम्बी हैं और कुनैक्शन देने में देर लगती है तो फिर उनसे यह पैसा न लिया जाये?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अगर हम उनसे अढाई हजार रुपया लेने से इन्कार कर दें तो हो सकता है तीस साल भी नम्बर न आये ।

राव बंसी सिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिन की टैस्ट रिपोर्ट आ चुकी हैं और कुनैक्शन मिले नहीं, उन एप्लीकेशन्ज की कुल कितनी तादाद है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : छः महीने पुरानी जो टैस्ट रिपोर्ट पैन्डिग हैं व 4,945 हैं ।

चौधरी मनफूल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह प्रयत्न करेंगें कि जिन सरकल्ज में ज्यादा टैस्ट रिपोर्टस पैन्डिग हैं उसके हिसाब से ही वहां मैटीरियल भेजा जाये?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : ऐसा अब किया गया है कि जिस सरकल की टैस्ट रिपोर्ट ज्यादा पैन्डिग हैं उनको ज्यादा मैटीरियल देने का यत्न किया जायेगा ।

श्री अमर सिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि भिवानी जिले में एक साल से ज्यादा और छः महीने से ज्यादा कितनी ऐसी पुरानी एप्लीकेशनज पैन्डिग हैं जिनकी टैस्ट रिपोर्ट आ चुकी हैं लेकिन कुनैक्शन नहीं दिये गये?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, यह बात मैं तीन साल से यहां हाउस में बताता आ रहा हूं कि हमारे पास डिस्ट्रिक्टवाइज इन्फर्मेशन नहीं होती बल्कि सरकलवाइज होती है ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ये जितनी भी एप्ली– केशनज पैन्डिग हैं इनमें सरकारी ट्यूबवैल्ज की कितनी हैं? इस बात को भी ध्यान रखते हुए कि सरकारी ट्यूबवैल्ज पर लाखों रुपया खर्च होता है और

किसान भी उस से जल्दी से जल्दी पानी लेना चाहता है तो क्या उनको जल्दी से जल्दी कुनैक्शन देने की कोशिश करेंगे?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : यह बात दुरुस्त है कि सरकारी ट्यूबवैल्ज को कुनंक्शन जल्दी नहीं मिलता है क्योंकि उसकी मोटर बड़ी होती है, बड़ा ट्रांसफार्मर रखना पड़ता है लेकिन फिर भी सरकारी ट्यूबवैल्ज को प्रायरिटी देते हैं इस के इलावा और भी जल्दी से जल्दी कुनैक्शन देने का यत्न करेंगें ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : रोहतक सरकल में सब–डिविजन झज्जर में कुल कितने कुनैक्शन पैन्डिग हैं? झज्जर का बैकवर्ड एरिया है क्या वहां पर जल्दी से जल्दी कुनैक्शन देने की कोशिश करेंगें?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : रोहतक सारे सरकल में जो टैस्ट रिपोर्टस छ रू महीने से पुरानी नवम्बर तक पैन्डिग हैं वे 1,100 के लगभग हैं । अब झज्जर में कितनी पैन्डिग हैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

श्री बिहारी लाल बाल्मीकिः क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि जिन गांवों में तहसील बल्लभगढ में जमींदारों को ट्यूबवैल्ज के कुनैक्शन दिये गये हैं लेकिन वे हरिजनों को पानी नहीं देते हैं क्या उनके कुनैक्शन काटने की कृपा करेंगे और क्या सरकार उनकी पानी दिलाने में मदद कर सकती हे?

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

श्री अमर सिंह : जैसा कि मिनिस्टर साहब को इल्म है कि कन्डक्टर की वजह से मेनली कुनैक्शन पैन्डिग हैं । क्या सरकार कन्डक्टर की अवेलेबिलिटी के लिए कोशिश करेगी?

सरदार हरभोहिन्द्र सिंह चट्ठा : खाली कन्डक्टर की वजह से नहीं, बल्कि और भी कई वजुहात हैं लेकिन यह बात दुरुस्त है कि मैटीरियल नहीं मिलता है । मैटीरियल न मिलने की वजह से कुनैक्शन नहीं दिये जा रहे हैं । जब हमारी स्टेट ने रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन की उस वक्त सारा हिन्दुस्तान सोया हुआ था लेकिन अब सारा हिन्दुस्तान ट्यूबवैल्ज और गांवों को बिजली दे रहा है फिर भी हम दूसरी स्टेट्स से ज्यादा मैटीरियल ले रहे हैं ।

राव बंसी सिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि रोहतक सरकल के अन्दर एक साल से ज्यादा और दो साल से ज्यादा कितने कुनैक्शन देने पैन्डिग हैं जिनकी टैस्ट रिपोर्ट भी आ चुकी है

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : एक साल या दो साल से ज्यादा की फिगर्ज इस वक्त मेरे पास नहीं हैं । अगर आनरेबल मैम्बर सैपरेट नोटिस दें तो उस वक्त बता देंगें ।

श्री रामजी लाल डागर : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि एक्स० ई० एन ० बल्लभगढ और एक्स० ई० एन० पलवल के पास दो सारन से पहले की कितनी एप्लीकेशन पैन्डिग हैं?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : एक्स० ई० एन ० का हमारे साथ कोई हिसाब किताब नहीं होता । हमारे पास तो सरकलवाइज हिसाब किताब है ।

चौधरी अब्दुर रजाक खां : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अप्रैल 1975 से 30 नवम्बर 1975 तक कुल कितने कुनैक्शन दिये गये?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय अभी तक हम चार हजार दो सौ कुनैक्शन दे चुके हैं । हमारा टारगेट चार हजार का था लेकिन हमारा इरादा है कि इस साल में छः हजार कुनैक्शन ट्यूबवैल्ज को दें । (तालियां)

चौधरी पीर चन्दः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे जो एप्लीकेशन्ज बाकी हैं, इन सब को 1976–77 में कूनैक्शन्ज दे पायेंगे या कुछ एप्लीकेशन्ज बाकी रह जायेगी?

सरदार हरमोहिद्ध सिंह चट्ठा : कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी कुनैक्शन दें ।

राव दलीप सिंह : क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसे आपने किया है कि कुनैक्शन के लिये कोई अढाई हजार रुपया जमा करा दे तो उसको प्रैफरैन्स दिया जाता है, अगर कोई आदमी खुद सामान खरीदकर दे तो क्या उसको बिलों के अगेन्स्ट एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : बिलों के अगेन्सट उनको एडजस्ट करेंगे ।

श्री अमर सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हिसार सरकल में ऐसी कितनी टैस्ट रिपोर्ट्स पैंडिग हैं जिन्होंने लैड मौर्गेज बैंक से टयुबवैल्ज के लिये कर्जा लिया हो और उनको अभी तक भी कुनैक्शन न मिला हो?

सरदार हरमोहिन्द सिंह चट्ठा : हिसार सरकल में 499 टैस्ट रिपोर्ट्स. पैंडिग थी लेकिन उसके बाद भी कईयों को कुनैक्शन दिये जा चुके हैं । हम यह नहीं बता सकते कि किस किसान ने कर्जा लिया था और किस किसान ने कर्जा नहीं लिया था ।

तारांकित प्रश्न सं ० 1525

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी चांद राम, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Incomplete Link Roads

***1532. Lala Rulya Ram :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to complete the unfinished work on the link roads ;

(c) if so, the time by which the unfinished work is

likely to be completed; and

(d) the time by which the link roads (i) Kaimla to Pundri and (ii) Kalheri to Barsat are likely to be constructed for which the entire expenditure has been deposited by the Market Committee Gharannda (District Karnal).

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma) :

(a) Yes.

(b) No definite date can be given Efforts will, however, be made to complete the incomplete roads subject to the availability of funds.

(c) These roads form duplicate links and cannot be constructed as per existing policy of the Government. No specific deposit for these roads has been made by the Market Committee, Gharaunda.

लाला रूसिया राम : क्या आनरेबल मत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब कैमला टू पुंडरी और कलहेडी टू बरसत की लिंक रोड्ज के लिये मार्किट कमेटी घरौंडा ने 10 लाख रुपया जमा करवा दिया है और उन पर मिट्टी भी गिरी हुई है तो वह एक साल तक भी कम्पलीट क्यों नहीं हुई हें?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : स्पीकर साहब, हमारी जो फोर्थ फाइव ईयर प्लान थी, वह गवर्नमैंट ने 92 करोड़ की प्लान तैयार की थी और यह फैसला किया गया था कि सारी स्टेट के ऐसे गांवों की लिंक रोड्ज को कम्पलीट कर दिया जाये और इसी

हिसाब से प्रैक्टिकली सारी सड्कों पर अर्थ–वर्क कर दिया गया लेकिन जून, 1972 में गवर्नमैंट आफ इंडिया ने, जब प्लानिंग कमीशन ने एतराज किया, तो यह निर्णय लिया कि पानी और बिजली की ओर ज्यादा अटैन्शन दी जाये जिसकी वजह से वह काम सलो–डाउन कर दिया गया । इस तरह जून, 1972 से हमारी प्रोग्रैस सलो–डाउन हुई है । इस तरह और बहुत सी सड़कों पर भी अर्थ–वर्क हुआ पड़ा है और कईयों पर पार्ट मैटीरियल पड़ा हुआ है लेकिन हम उनको कम्पलीट नहीं कर सकते । जिन दो सड़कों का आनरेबल मैम्बर ने जिक्र किया है, जैसे कि मैंने अर्ज किया है, वे डुप्लीकेट लिंक्स हैं और इनके बारे में हमारी ऐसी पालिसी नहीं बनायी जा सकती कि एक गांव को दोनों तरफ से जोड़ दिया जाये । जो कैमला–पुंडरी रोड है, वह पुंडरी बरसत रोड पर फाल करती है इसी तरह कलहेडी से बरसत घरौंडा से कनैक्टिड है । इस तरह वे दोनों रोड्ज एक तरफ से आलरैडी कनैक्टिड हैं ।

लाला रुलिया राम : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इनके लिये हमने जो मार्किट कमेटी का पैसा जमा करवाया है, उसका क्या बना?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : इसमें यह पोजीशन है कि 31,823 रुपये इस मार्किट कमेटी के अगेन्सट अनस्पैन्ट थे । 1974–75 में 3,82,700 रुपये इस मार्किट कमेटी को आये जिसमें से 94,022 रुपये रोड्क पर 197 4– 75 में खर्च कर दिये और

इस तरह से टोटल बैलेन्स 3,61,101 रुपया अनस्पैन्ट है । But this cannot be utilised positvely for this Market Committee क्योंकि 1 अप्रैल, 1974 से जो भी मार्किट कमेटीज के फंड्ज थे वे जनरल रैवेन्यूज में आ गये हैं ।

चौधरी फूल चन्द (रोहट) : स्पीकर साहब, अब जो सड़कें पी ० डब्ल्यू ० डी ० वाले ले रहे हैं उसकी. चौड़ाई इन्होंने 66 फूट कर दी है जबकि जो पहले होती थीं उनकी चौड़ाई 30–32 फुट होती थी । उन सड्कों को और चौड़ा करने के लिये अब धडाधड बिल्डिंगें गिराने लग रहे हैं । क्या अब की चौड़ाई को पिछली चौड़ाई के मुताबिक ठीक करेंगे क्योंकि इससे बहुत लोग परेशान हैं?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : स्पीकर साहब, यह जो एलीगेशन है, यह गल्त है । जो लोगों की पी ० डल्ब्यू ० डी ० लैड पर एनक्रोचमैंट थी, सड्कों को चौड़ा करने के लिये वह एनक्रोचमैंट हमने गिरा दी है । गवर्नमैंट की रोड पर एडवर्स पोजैशन से मालिक नहीं बन सकते और एक्चूअली मालिक नहीं थे, हमने उनको हटाया है ।

श्री अमर सिंह : जैसे कि मंत्री महोदय ने यह बताया है कि बहुत सी सड़कों पर मैटीरियल भी पड़ा हुआ है और अर्थ–वर्क भी हुआ पड़ा है लेकिन पिछले दिनों से उनका काम सलो– डाउन हो गया, क्या यह सलो–डाउन का वर्ड 1976–77 में रिमूव भी होगा या यों ही चलता रहेगा?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : मुझे अन्देशा है कि यह सलो–डाउन का वर्ड रिमूव नहीं होगा बल्कि यों ही चलता रहेगा । 1978– 77 में, जोकि कमिंग ईयर है, हमें जो प..लोकेशन की जा रही है, वह और कम. है । कहने को तो यह कहा जा रहा है कि मार्किट कमेटियों की 65 प्रतिशत इन्कम रोड्ज के लिये जाती है लेकिन यह एक्चुअली does not go to P.W.D. roads. It is not a fact.

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि इस लिंक रोड के चक्कर में कई मेन रोड्ज भी इन्होंने बीच में अधूरी ही छोड़ दी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं किया कि जो मेन रोड थी, उसको इधर से मिला दिया और एक तरफ उधर से मिला दिया और बीच में छोड़ दिपा जैसे कि अबोआ छप्पर रोड है ओर उसको पूरा समझ लिया? उसमें एक किलोमीटर का टुकड़ा छोड़ दिया गया और कह दिया कि यहां तो वीच में गांव है, इसलिये यह मिल गयी । कहीं सब जगह ऐसा तो नहीं किया?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Mr. Speaker, the hon. Member is perfectly correct. There are so many roads in which gaps have been left because villages on both sides have been connected. But the Government is considering the desirability of giving preference to filling up those gaps so that those roads may be completed.

चौधरी शिव राम वर्मा : मंत्री महोदय ने बताया है कि सैकण्ड लिंक की वजह से कई सड़कें बीच में पड़ी हैं और ऐसी

सड्कों को हम देखेने । ऐसी ही एक सड़क जनझाडी से लेकर सुलतानपुर होती हुए तरावडी के लिये मन्जूर हुई थी लेकिन थोड़ी देर के बाद ललाणी तक बनाकर दो–अढाई किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया गया वह रोड कई ग्रामों से होकर तरावडी मण्डी में जाती है और उसके न बनने की वजह से लोगों को बारह–तेरह मील धूम कर जाना पड़ता है । अगर वह दो–तीन किलोमीटर का टुकडा बना दिया जाये तो उससे कई गांवों को फायदा होगा । इसलिये क्या सरकार उसको पहले बनाने पर विचार करेगी?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : यह तो ठीक है कि अगर छोटे–छोटे लिंक्स बना दिये जायें तो लोगों को काफी फायदा हो जाता है लेकिन सवाल तो अवेलेबिलिटी आफ–फन्डज का है ।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि जो 65 प्रतिशत रुपया मार्किट कमेटियों के रैवेन्यू से आता है वह केवल रोड्ज के लिये महफूज होता है लेकिन दरअसल इतना रुपया मिलता नहीं । क्या मंत्री महोदय यह फरमायेंगे कि पी० डबल्यू ० डी ० को जिस कदर मार्किट कमेटियों की आमदनी में से रुपया मिलता है, उस कदर वहां की रोड्ज पर कितना रुपया खर्च होता है?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : 1974– 75 में तो मार्किट कमेटियों का कोई रुपया नहीं आया । फिर हाई कोर्ट की रुलिंग आने के बाद हमें 197 5– 76 में साढ़े चार करोड़ रुपये की

एन्टीसिपेटिड इन्कम थी उसमें से 10 प्रतिशत कट लगा, बाकी 4 करोड़ रह गया । उसमें से फिर एग्रीकल्चरल डिवैल्पमैंट और इम्प्रूवमैंट के लिये भी खर्च किया जाता है । इस तरह से दूसरी तरफ भी कुछ रुपया एग्रीकल्चरिस्ट के भले के लिये उसमें से खर्च किया जाता है ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि 65 प्रतिशत रुपया रोड्ज के लिए मुझे नहीं मिलता जबकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने फरमाया था कि 85 प्रतिशत रुपया सड़कों के लिए सैन्ट्रल पूल में जाता है । क्या मैली महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कौनसी स्टेटमैंट ठीक है?

Pandit Chiranji Lal Sharma : As P.W.D. Minister I can say with a sense of responsibility that 65% रुपया मुझे इस साल जो मिलना चाहिए था वह अभी नहीं मिला है ।

Mr. Speaker : Question Hour is over.

ताराँकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of shopping Centres in Karnal

***1406. Chaudhri Ram Lal :** Will the Minister for Local Government be pleased to state—

(a) the total number together with the names of schemes of Municipal Committee, Karnal, for construction of shops and stalls approved by the Government during the years 1973-74, 1974-75 and 1975-76 (to-date); and

(b) whether any conditions were imposed by the Government while approving any of the schemes referred to in part (a) above ; if so the details thereof in each case ?

स्थानीय शासन मन्त्री (चौधरी पोकर राम गोदारा) : (क) शून्य।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Under Trials Held in Jails

***1434. Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Home be pleased to state the total number of under-trials held in the jails at Rohtak, Karnal, Ambala and Hissar during the calendar years 1972, 1973, 1974 and 1975 separately ?

परिवहन मंत्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल) : अपेक्षित सूचना विवरण के रूप में सदन के पटल पर रग्बी जाती है ।

स्टेटमैट

विचाराधीन बन्दियों का व्यौरा जो दाखिल किये गये

वर्ष	जिला जेल रोहतक	जिला जेल करनाल	केन्द्रीय जेल अम्बाला	जिला जेल हिसार
1972	2,270	2,032	1,815	2,736
1973	3,763	2,982	4,429	3,896

1974	3,086	3,101	2,411	3,243
1975	2,979	2,062	1,643	2,382

(1 – 1 – 75 से 26– 11 – 75 तक)

Low Lying Areas in the State

***1454. Chaudhri Devi Lal :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the district-wise total area of land in the State which is at present lying uncultivable due to its being low lying area ; and

(b) whether the Government has taken any steps to make the land referred to in part (a) above cultivable; if so, the district-wise area of such land made cultivable so far ?

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा) :

(ए) लो लाईगं क्षेत्र के कारण काश्त न होने वाली भूमि केवल किला रोहतक, सोनीपत तथा गुड़गांव में है जो क्रमश रू 16753, 20157 तथा 11400 हैक्टेयर है ।

(बी) हां । उपरोक्त में से काश्त योग्य बना दिया गया क्षेल जिला रोहतक, सोनीपत तथा गुड़गांवमें क्रमश रू 1 5078, 15148 तथा 8222 हैक्टेयर है ।

Economy in Administration or Expenditure.

***1524. Chaudhri Chand Ram :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether any measures, if any,

were taken by the Government to effect economy in its administration or expenditure ?

Finance Minister (Shri Ram Saran Chand Mital) : Yes, sir.

For effecting economy in Govt. expenditure, instructions have been issued from time to time covering a wide range of subjects like use of telephones, electricity, contingent expenditure, touring, meetings, staff and schemes, stationery, furniture, petrol, purchase & repair of vehicles, advertisement and publicity, construction works, official functions, hospitality etc.

Complaint against the Administrator of Municipal Committee, Karnal

***1407. Chaudhri Ram Lal :** Will the Minister for Housing and Local Government be pleased to state whether any complaints were received by the State Government or District Magistrate (Deputy Commissioner) against the Administrator of the Municipal Committee, Karnal, during the years 1973-1974 and 1975 (to-date), if so, the nature of the said complaints and the action taken thereon ?

स्थानीय शासन मन्त्री (चौधरी पोकर राम गोदारा) : हाँ । छः शिकायतें प्राप्त हुई थीं । चार शिकायतें राम नगर में पलौटस तथा दुकानें अलाट करने के लिए रिश्वत माँगने के बारे थीं । एक शिकायत एक ड्राईवर, जोकि नगरपालिका का कर्मचारी था, की एक दुर्घटना में मृत्यु से सम्बन्धित थी । दूसरी शिकायत नगरपालिका का अभिलेख न प्रस्तुत करने के विरूद्ध थी । क्योंकि

इन शिकायतों में लगाये गए आरोप परेशान करने वाले तथा निस्सार पाए गए थे, इसलिए इन्हें फाईल कर दिया गया था ।

Mini-Secretariat at Jind

***1435. Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state the time by which the construction of Mini-Secretariat at Jind is likely to be completed ?

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा) : इस समय यह बताना सम्भव नहीं कि किस अवधि तक यह प्रारम्भ होगा क्योंकि इसका निर्भर निधि की उपलब्धि पर है ।

Sarpanches and Panches under Suspension

***1455. Chaudhri Devi Lal :** Will the Minister for Developmenent be pleased to state—

(a) the district-wise total numbers of Sarpanches and Panches who are under suspension for the last one year, two years and three years, separately ; and

(b) the district-wise total number of Sarpanches and Panches who have been removed from the Panchayats during the period from 1972-73, 1973-74 and 1974-75, to-date ?

कृषि मंत्री (कर्नल महा सिंह) : (क तथा ख) वांछित सूचना, विवरण में सदन के सम्मुख रखी जाती है ।

STATEMENT

District-wise total number of Sarpanches/ Panches who are under suspension for the last :—

(b) District-wise total number of Sarpanches/Panches who have been removed from the Panchayats during the period from

District		One Year	Two Years	Three Years	1972-73	1973-74	1974-75 to-date
Ambala	Sarpanches	—	2	—	—	—	—
	Panches	5	2	3	1	—	3
Rohtak	Sarpanches	3	1	—	—	—	2
	Panches	9	—	—	—	—	1
Karnal	Sarpanches	3	—	1	—	—	—
	Panches	11	1	—	—	2	6
Hissar	Sarpanches	6	1	—	—	—	3
	Panches	1	—	—	--	—	7
Bhiwani	Sarpanches	6	—	—	—	—	4
	Panches	3	—	1	—	—	4
Sirsa	Sarpanches	2	—	—	—	—	-
	Panches	—	—	—	_	—	—
Sonepat	Sarpanches	3	2	—	—	—	6
	Panches	9	—	—	—	1	4

Narnaul	Sarpanches	12	—	1	—	—	1
	Panches	12	—			—	5
Jind	Sarpanches	9	1	—	1	1	6
	Panches	6	—	—	—	3	7
Kurukshetra	Sarpanches	22	—	—	—	—	-
	Panches	23	1	1	—	—	3
Gurgaon	Sarpanches	6	3	—	—	—	-
	Panches	8	—	—	—	—	1

Elimination of Middlemen

***1525. Chaudhri Chand Ram :** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether the Government intends to eliminate all kinds of Middlemen (Contractors) for executing its various works ; and

(b) whether the State Government has received any communication on the subject from the Central Government ?

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा) :

(क) नहीं । बल्कि जायज लेबर कंस्ट्रक्शन कापरेटिव सोसाईटीज को प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

(ख) नहीं ।

वर्ष 1976–77 का बजट पेश करना

Mr. Speaker : The Finance Minister.

वित्त मन्त्री (श्री राम सरन चन्द मित्तल) : महोदय, मैं इस गरिमापूर्ण सदन के समक्ष वर्ष 1976– 77 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ ।

आर्थिक स्थिति

बजट प्रस्तावों का उल्लेख करने से पूर्व, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान राज्य की आर्थिक स्थिति के कुछ पहलुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । माननीय सदस्यों को विदित हो है कि वर्ष 1972– 73 से 1974–75 तक लगातार सूखा पड़ने के कारण राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन कम होता चला गया । मौसम की प्रतिकूलता के कारण वर्ष 1974– 75 के दौरान खाद्यान्न–उत्पादन केवल 33.37 लाख टन हुआ जबकि वर्ष 1973–74 में यह 38.37 लाख टन था । वर्ष 1974– 75 में कपास का उत्पादन भी वर्ष 1973– 74 की 441 लाख गांठों से घटकर 4.25 लाख गांठें रह गया । वर्ष 1975–7 6 में इन्द्र देवता की कृ पा रही है और हमें आशा है कि यह वर्ष हमारे लिए समृद्धिशाली

होगा । वर्ष 1975–76 के दौरान कुल खाद्यान्न–उत्पादन 46.60 लाख टन होने की सम्भावना है । (तालियां)

विभिन्न कठिनाइयों के होते हुए भी राज्य में औद्योगिक विकास लगातार होता रहा । छोटे कारखानों की संख्या बढ़ी है । राज्य के संगठित क्षेत्र में समूचे रूप में रोजगार जून, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में 3.54 लाख से बढ़कर जून, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में 3.70 लाख हो गया । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 1975– 76 के पहले 6 महीनों के दौरान राज्य के रोजगार कार्यालयों ने संगठित क्षेत्र में 13,229 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध किया । (तालियां)

कीमतों के सन्दर्भ में वर्ष 1975 आशा लेकर आरम्भ हुआ । सरकार द्वारा अपनाए गए' विभिन्न आर्थिक और वित्तीय उपायों और आपात् स्थिति की घोषणा तथा प्रधान मंत्री के 20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कारण, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक मई, 1975 में 313 से घट कर अक्तूबर, 1975 में 308 हो गया । सितम्बर, 1974 से अक्तूबर, 1975 तक कीमतों में कुल कमी 6.1 प्रतिशत थी । अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग खपतकार. मूल्य सूचकांक (आधार 1960) भी सितम्बर, 1974 के 334 से गिर कर अक्तूबर, 1975 में 316 हो गया । दूसरे शब्दों में 5. 4 प्रतिशत कम हो गया । हरियाणा में भी मूल्यों का रुझान इसी प्रकार का रहा । इसी अवधि के दौरान औसत हरियाणा कामगार श्रेणी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (आधार 1966) 8. 8 प्रतिशत की कमी

आई । बढ़ती हुई कीमतों पर, अन्य उपायों के साथ–साथ उत्पादक–क्षेत्रो में खर्च को जारी रख कर और अनुत्पादक क्षेत्रो में यथासम्भव खर्च कम करके तथा सस्ती और उचित कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को नियमित रूप से उपलब्ध करवाकर काबू पा लिया गया है । यहां यह भी ध्यान योग्य है कि सार्वजनिक वितरण पद्धति को सुदृढ़ बनाया गया और गेहूं का आटा चावल, खाण्ड, मिट्टी का तेल आदि आवश्यक वस्तुएं राज्य के देहाती और शहरी क्षेत्रों में 4, 456 सस्ती दुकानों द्वारा लोगों को सप्लाई की गई । इसी तरह, कण्ट्रोल वाले कपड़े के वितरण की दुकानो की संख्या भी नवम्बर, 1975 में बढ़ कर 1,396 हो गई । मार्च, 1975 में यह संख्या 286 थी ।

प्रधान मन्त्री का 20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम

समाज की सामान्य आर्थिक स्थिति को और अधिक सुधारने के उद्देश्य से राज्य सरकार प्रधान मंत्री द्वारा 1 जुलाई, 1975 को घोषित किए गए 20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रही है । इस योजित सामाजिक एवं आर्थिक सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम (New Deal) के अन्तर्गत राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति कर ली है ।

सरकारी खर्च में कमी

सरकारी खर्च के विभिन्न क्षेत्रों में कमी करने के उद्देश्य से दौरों, नए स्टाफ और स्कीमों पर खर्च, फर्नीचर की खरीद और पैट्रोल पर खर्च आदि विभिन्न मद्दो पर प्रतिबन्ध लगाए गए हैं ।

मूल्यों की स्थिति

हमारे प्रधान मन्त्री द्वारा 2 0–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के बाद खाद्यान्नों, दालों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य भी घटने शुरू हो गए हैं । 152 व्यापारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा भारत रक्षा नियमों के उल्लंघन के लिए मामले दर्ज किए गार हैं । इस कार्यक्रम की घोषणा के बाद 201 जमाखोरों की गिरफ्तारियां की गई हैं ।

भूमिहीनों के लिए रिहायशी जगह

चालू वर्ष के दौरान सरकार ने 1,4 8,859 व्यक्तियों को शामलात भूमि में से मकान बनाने के लिए जगहें मुक्त दी हैं । (तालियाँ) प्रत्येक व्यक्ति को 100 वर्ग गज का प्लाट दिया गया है । इस सम्बन्ध में 82 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त क्र लिया गया है । और शेष 32, 345 व्यक्तियों को मकानों के लिए स्थान शीघ्र जुटाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

देहाती कर्जदारी का समापन

हरियाणा विधान सभा द्वारा एक विधेयक पास किया गया है जिसके द्वारा सभी कर्जों (सरकारी कर्जों को छोड़कर) की

वसूली के दावों पर रोक लगा दी गई है और सभी लम्बित दावों को भी एक वर्ष की अवधि के लिए स्थगित कर दिया गया है । (तालियां) कमजोर वर्गो के लिए सांस्थानिक ऋण लघु और सीमान्त किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए राज्य में पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है । रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा लघु तथा सीमान्त किसानों के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत न्यूनतम सीमा के लक्ष्य को सहकारी बैंक पूरा कर ही रहे हैं ।

भिवानी में 531 सदस्यों वाली एक किसान सेवा समिति काम कर रही है । तीन और किसान सेवा समितियां रजिस्टर की जा चुकी हैं । भिवानी में एक क्षेत्रीय देहाती बैक भी खोला गया है और गुड़गांव में एक और देहाती बैक के निकट भविष्य में चालू हो जाने की सम्भावना है ।

न्यूनतम मजदूरी नए आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा के बाद हरियाणा में 1 1 व्यवसायों की मजदूरी के न्यूनतम दर बढ़ा दिए गए हैं । अकुशल कामगारों के लिए मजदूरी के न्यूनतम दर 140 रुपए से 175 रुपए प्रति मास निश्चित किए गए हैं जो कि पहले 82 रुपए से 115 रुपये प्रति मास के बीच हुआ करते थे । (तालियां)

भूगत जल स्त्रोतों को प्रयोग में लाना

पु0 आर0 सी0 ने तीन वर्षों की अवधि के लिए 26 करोड़ रुपए की लागत पर 23,457 उथले नलकूप लगाने की स्कीम अनुमोदित कर दी है और चालू वर्ष के दौरान 2,812 कृषकों को कर्जे पहले ही दिए जा चुके हैं ।

अब तक खोदे गए सीधी सिंचाई नलकूपों और आवर्द्धन नलकूपों की कुल संख्या 2,564 है और हुन में से 2,085 चल रहे हैं । राज्य भूमि जल बोर्ड द्वारा 200 नलकूपों– आवर्द्धन नलकूपों के ड्रिलिंग के लिए 8 स्कीमों की छानबीन की जा चुकी है और उन–हें ए ० आर० सी ० के फस अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है । छू ० आर ० सी० ने 21.53 लाख रुपए की लागत पर 165 छिड़काव सैट(Sprinkler Sets) लगाने के लिए एक स्कीम भी स्वीकृत की है । इस स्कीम के अन्तर्गत 151 छिडकाव सैटों के लिए और एक अन्य कार्यक्रम के अधीन 31 छिड़काव सैटों के लिए कर्जे पहले ही स्वीकृत किए जा चुके है ।

हथकरघा उद्योग का विकास

परम्परागत बुनकरों को प्रशिक्षित करने के लिए हरियाणा हयकरघा शिखर सहकारी समिति ने नारनौल तथा नूह में दो केन्द्र खोले हैं । 10 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर ऐसे 20 केन्द्र खोलने के लिए एक स्कीम स्वीकृत की जा चुकी है । हथकरघा उद्योग के विकास को तेज करने के लिए सरकार हुक

हथकरघा निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है ।

छात्रों को पाठ्य पुस्तकें सप्लाई करना

विद्यार्थियों को सुविधाए प्रदान करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है । विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों औंर कुछ विद्यालयों के 97 छात्रावासों में रहने वाले 6,580 विद्यार्थियों को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लित व्यवस्था की गई है । चीनी का राशन 420 ग्राम से 750 हाय प्रति मास प्रति विद्यार्थी कर दिया गया है । छात्रावास में बिजली की खपत के दर वाणिज्यिक दरों से कम कर के घरेलू खपत के दर के बराबर कर दिये गये हें । 21,91,376 रुपए के मुल्य की कापियां बनवाई गई हैं और विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों और विद्यालयों के 17,13,889 विद्यार्थियों को वितरित की गई हैं । विद्यार्थियों को कापियों के वितरण कार्य के फलवस्वरूप 3,62,000 रूपये की रियायत प्राप्त हो चुकी है । हरियाणा में आठवीं श्रेणी तक की पुस्तकों का राष्टयिकरण कर दिया गया है और सरकारी डिपुओं के माध्यम से नियत मूल्यों पर बेची जा रही है । विद्याथियों को दी जाने वाली पाठ्य पुस्तकों का मूल्य उनके मुद्रण मूल्य से 5 प्रतिशत कम हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय और कालेजों में पुस्तक बैक खोलने के लिए 5,74, 500 रुपए की राशि स्वीकृत की है । अब तक 151 कालेजों में पुस्तक बैकं खोलने के

लिए 4,10,802 रुपए की राशि दी जा चु की है । सरकार को कुल खर्च का 20 प्रतिशत भाग वहन करना है । हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में पुस्तक. बैंक खोलने के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं ।

कमजोर वर्गों के प्रशिक्षु

अनुसूचित जातियों, भूतपूर्व सैनिकों, विकंलाग व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने पर विशेष बल दिया जा रहा है । विभिन्न संस्थानों में 3,000 प्रशिक्षु लगाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ।

तथापि सरकार 20–सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में अब तक प्राप्त की गई सफलतालों को पर्याप्त नहीं समझती । अत. इस कार्यक्रम के सभी पहलुओं को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी । यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार अधिक धनराशि का उपबन्ध किया जाएगा ताकि इस कार्यकम के अन्तर्गत निश्चित किए गए लक्ष्य पूरे हो सकें ।

लेखे 1974– 75

वर्ष 1974– 75 के संशोधित अनुमान तैयार करते समय यह प्रत्याशा की गई थी कि वर्ष के अन्त में 6.33 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा । महालेखाकार द्वारा तैयार किए गए लेखों के अनुसार, वर्ष के अन्त में 1163 करोड़ रुपये का घाटा रहा । वास्तव में वर्ष 1974–75 का घाटा 12.79 करोड़ रुपए था जिसमें

कि रिजर्व बैक आफ इंडिया को वापिस करने योग्य बकाया अर्थोपाय पेशगिया भी शामिल हैं । इस प्रकार वर्ष 1974– 75 के वास्तविक व्यय में संशोधित अनुमानों के मुकाबले में राज्य सरकार का घाटा 646 करोड़ रुपए द्वारा बढ़ा । इस कमी के दो मुख्य कारण थे । पहला कारण तो यह था कि राज्य सरकार राजस्थान सरकार से व्यास परियोजना के अन्तर्गत दिए गए ऋणों पर 2.38 करोड़ रुपए का ब्याज वसूल न कर पाई । दूसरा कारण यह था कि सरकार ने खाद्यान्नों के भण्डार जिनकी कीमत लगभग 4. 80 करोड़ रुपए थी कैरी फारवर्ड (Carry Farward)करने का निर्णय ले लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसे सामान्य मूल्य पर सर्व–साधारण को उपलब्ध किया जा सके । खासकर जबकि राज्य के कुछ इलाके सूखाग्रस्त थे । यदि यह दो कारण नहीं होते तो वर्ष 1974– 75 के लेखों के आधार पर आर्थिक दशा वर्ष के संशोधित अनुमानों के समक्ष सुधरी हुई प्रतीत होती ।

1975–76 के संशोधित अनुमान और 1976– 77 के बजट अनुमान

चालू वर्ष के बजट अनुमानों के संशोधन तथा वर्ष 1976–7 7 के बजट अनुमानोंके आधार पर स्थिति निम्न प्रकार बनती है :–

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान 1978– 77

	1975–78	1975– 76	
		(रुपए करोड़ों में)	
(1) प्रारम्भिक बकाया–			
लेखा पुस्तकों के अनुसार	(--) 6.33	(-) 11.63	(--) 8.92
(2) राजस्व लेखा–			
प्राप्तियां	196.91	223.68	236.36
खर्च	181.30	188.67	202.82
बचत (+) (घाटा) (–)	(+) 15.61	(+) 35.01	(+) 33.54
(3) पूंजी खर्च (निवल)	26.86	32.44	34.55
(4) सार्वजनिक ऋण			
लिया गया ऋण	91.60	113.58	110.01
वापिस किया गया	86.93	96.55	100.91

ऋण			
निवल	(+) 4.67	(+) 17.03	(+) 9.10
(5) कर्जे तथा पेशगिया–			
पेशगिया	26.15	42.65	41.92
वसूलियां	8.62	7.65	7.05
निवल	(--) 17.53	(-) 35.00	(--) 34.87
(6) अन्तर्राज्यीय समंजन	--	(--) 0.04	
(7) आकस्मिकता निधि (निवल)	–		-
(8) अनिधिक ऋण (निवल)	(4-) 5.45	(-1-) 7.98	(+) 8. 25
(9) जमा तथा पेशगिया	(+)8.08	(+) 10.25	(+) 11.15
(10) प्रेषण	(---) O. 08	(---) O. 08	
(11) अन्तिम			

बकाया–

लेखा पुस्तकों के अनुसार	(-) 16.99	(--) 8.92	(-) 16.30

वर्ष 1975–76 के संशोधित अनुमानों के अनुसार चालू वर्ष का घाटा 8. 92 करोड़ रुपए अनुमानित है जबकि चालू वर्ष के बजट अनुमानों में प्रत्याशित घाटा 1699 करोड़ रुपए था । यह महत्वपूर्ण सुधार वित्तीय परिव्ययों में पर्याप्त माला में वृद्धि के बावरऊद भी सम्भव हो सका है । वर्ष 1975– 76 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य योजना का परिव्यय 83.74 करोड़ रुपए अपेक्षित था । हुसके मुकाबले में अब हम 101.27 करोड़ रुपए तक के योजना परिव्यय के लिए धन जुटाने की आशा कर रहे हैं । इस प्रकार हमारी समस्त योजना में 17 करोड़ रुपए से अधिक वृद्धि होने की आशा है जबकि प्रत्याशित घाटा लगभग 8 करोड़. रुपए कम हो गया है । यह महत्वपूर्ण सुधार खासकर आय में अधिक साधन जुटाने के कारण वृद्धि, भारत सरकार द्वारा सिंचाई तथा बिजली के लक्ष्य पूर्ति हेतु विशेष माली सहायता, तथा खर्च पर नियन्त्रण और बचत के द्वारा सम्भव हो सका है । सम्मान– नीय सदस्य राज्य सरकार द्वारा अधिक धन जुटाने के उपायों को पिछले कुछ वर्षो में योजना व्यय में लगातार वुद्धि की पृष्ठभूमि में देखेंगे । वर्ष 1973–74 में कुल योजना व्यय 85.90 करोड़ रुपए था

जबकि यह वर्ष 1974– 75 में 86.82 करोड़ रुपए था । चालू वर्ष का प्रत्याशित योजना व्यय वर्ष 1974– 75 के वास्तविक खर्च से लगभग 16.6 प्रतिशत अधिक होगा । चालू वर्ष मैं अधिक धन जुटाने कैं जो उपाय किए जए उन से राज्य सरकार को 9.63 करोड़ रुपए की अधिक आय होने की सम्भावना है । यह अधिक आय 1.50 करोड़ रुपए तो राज्य भविष्य निधि में अनिवार्य कटौती की दर में 6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत की वृद्धि, 5. 46 करोड़ रुपए विक्रय कर की दरों में वृद्धि 2. 32 करोड़ रुपए वाटर रेट्स (Water Rates)की दरों में वृद्धि तथा 0. 35 करोड़ रुपए अचल सम्पत्ति पर सरचार्ज का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विकास के लिए चालू रखने के निर्णय के कारण हुई । केन्द्रीय टैक्सों में से राज्य सरकार के हिस्से में 1.16 करोड़ रुपए की वृद्धि की आशा है । संशोधित अनुमानों में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला अनुदान 8. 17 करोड़ रुपए अधिक प्रत्याशित है । यह वृद्धि कुछ तो योजना तथा केन्द्रीय चालित स्कीमों के अन्तर्गत दिए जाने वाले अनुदान के कारण और कुछ राज्य सरकार द्वारा गेहू तथा चावल की खरीद तथा निर्यात पर प्रोत्साहन बोनस के अन्तर्गत है । संशोधित अनुमानों में ब्याज प्राप्तियां भी बजट अनुमानों के मुकाबले में 4. 57 करोड़ रुपए अधिक प्रत्याशित हैं । इस बढ़ोतरी के दो मुख्य भाग हैं । पहला तो यह कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को चालू वर्ष में 1. 94 करोड़ रुपए का ब्याज देना है जबकि बजट अनुमानों में इस सम्बन्ध मैं किसी प्रकार का उपबन्ध नहीं किया गया था । दूसरे राजस्थान सरकार

से 2. 38 करोड़ रुपए के ब्याज की वसूली की आशा है । यह खराज राजस्थान सरकार से व्यास परियोजना के अन्तर्गत दिए गए ऋणों पर लिया जाना है जिसकी अदायगी हमने कर दी हुई है ।

माननीय सदस्य देखेंगे कि योजनेतर खर्च की व्यवस्था संशोधित अनुमानों में बजट अनुमानों से 8. 18 करोड़ रुपए अधिक है । इसका मुख्य कारण मंहगाई भले की वह 3 किश्तें हैं जिनका अनुमोदन राज्य सरकार ने जून, 1975 में किया । सड्कों तथा इमारतों का अनुरक्षण खर्च संशोधित अनुमानों में लगभग 50 लाख रुपए अधिक हो गया है । इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण सामग्री की कीमतों, खासकर बिटुमन की कीमतों में वृद्धि है । पैंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के अन्तर्गत संशोधित अनुमानों में व्यय काफी हद तक बढ़ जाने की सम्भावना है क्योंकि चालू वर्ष में बहुत बड़ी माता में अध्यापको के लम्बित पैशन केसों का निपटारा होना सम्भावित है । सम्माननीय सदस्य राज्य सरकार के नए किले सिरसा की स्थापना सम्बन्धी निर्णय से अवगत हैं । इस निर्णय के दृष्टिगत संशोधित अनुमानों में अधिक खर्च का उपबन्ध करना अनिवार्य हो गया । खर्च पर नियन्त्रण तथा बचत के उपायों के फलस्वरूप ही राज्य सरकार के लिए यह सम्भव हो सका है कि यह वृद्धि 6. 18 करोड़ रुपए तक ही सीमित रही ।

उक्त विभिन्न उपायों की सहायता से राज्य की वर्ष 1975– 78 की योजना सीमा उत्पादन का क्षेत्रों में काफी हद तक बढ़ाई जा सकी है । व्यास परियोजना के लिए हमारा अंशदान 13.

63 करोड़ रुपए से बढ़कर 20.80 करोड़ रुपए हो गया है । बिजली परियोजनाओं तथा बिजली के वितरण के लिए बजट परिव्यय को 25.70 करोड़ रुपए से बढ़ाकर संशोधित अनुमानों में 30.75 करोड़ रुपए कर दिया गया है । मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का परिव्यय बजट अनुमानों में 12 करोड़ रुपए रखा गया था । संशोधित अनुमानों में इसे बढ़ाकर 17. 47 करोड़ रुपए कर दिया गया है । इस अधिक परिव्यय में राज्य के बड़े क्षेत्र में जमीदारों को सिंचाई का लाभ देने हेतु जवाहर लाल नेहरू कैनाल परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए 5 करोड़ रुपए का परिव्यय भी शामिल है । कृषि तथा सामुदायिक क्षेत्र के लिए संशोाइ धत अनुमानों में बजट अनुमानों के मुकाबले में 2.73 करोड़ रुपए अधिक परिव्यय रखा गया है ।

वर्ष 1976– 77 के बजट अनुमानों के अनुमानो वाई के अन्त में 16.30 करोड़ रुपए का घाटा प्रत्याशित हए और इस घाटे में चालू वर्ष का 8.92 करोड़ रुपए का घाटा भी शामिल है । घाटे के बढने का मुख्य कारण वर्ष 1976– 77 की राज्य योजना सीमा का 111.15 करोड़ रुपए होना है, क्योंकि चालू वर्ष की राज्य योजना केवल 101.27 करोड़ रुपए है ।

मैं इस घाटे की मुढग विशेषताए वर्ष 1976– 77 के लिए वित्तीय नीति तथा उसके प्रबन्ध की व्याख्या करते समय बताऊंगा ।

योजना परिव्यय

योजना आयोग ने राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974– 79) की परिव्यय अस्थाई तौर पर 563 करोड़ रुपए मंजूर की थी । वर्ष 1974–75 में विभिन्न विकास परियोजनाओं तथा स्कीमों पर 86.82 करोड़ रुपए का व्यय किया गया । वर्ष 1975–76 के लिए योजना आयोग ने योजना कार्यक्रमों के लिए 92.25 करोड़ रुपए की योजना सीमा निर्धारित की है जबकि बजट अनुमानों में इन कार्यों के लिए 83.74 करोड़ रुपए की सीमा दर्शाई गई हए । किन्तु राज्य सरकार ने चासउ वर्ष की योजना सीमा को 92. 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 101. 27 करोड़ रुपए कर दिया है ताकि कुछ क्षेत्रो की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जा सके । इस वर्ष के अतिरिक्त विनिधान में से रासा–यनिक खाद के लिए उपदान 82. 50 लाख रुपए, लघु सिचाई के लिए 47 लाख रुपए, मुख्य तथा मध्यम सिंचाई के लिए 412 लाख रुपए, फरीदाबाद ताप बिजली घर को तीसरी यूनिट के लिए 100 लाख रुपए, शिक्षा के लिए 97 लाख रुपए जिसमें रोहतक विश्वविद्यालय के लिए 10 लाख रुपए रखे गए हैं, चिकित्सा सेवाओं के सुधार के लिए 32. 84 लाख रुपए तथा हाल ही में स्थापित किए गए भिवानी, सोनीपत तथा कुरुक्षेत्रो के तीन जिलों में सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत अत्यावश्यक भवनों के निर्माण हेतु 45. 22 लाख रुपए दिए गए हैं । कुछ क्षेत्रों में व्यय को समंजित

किया गया जिसके कारण निवल वृद्धि 9.02 करोड़ रुपए की हुई है ।

वर्ष 1976– 77 का योजना परिव्यय अस्थाई तौर पर 111. 15 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है । विकास कार्यक्रमों की प्रगति को सुनिश्चित करने, चालू सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने तथा अन्तरज्यि बहु–उद्देशीय योजनाओं के लिए धन राशि उपलब्ध करने के उद्देश्यों के दृष्टिगत यह योजना सीमा न्यूनतम है । इसके अति–रिक्त 8.81 करोड़ रुपए केन्द्रीय चालित स्कीमों क्ए? लिए वर्ष 1976–77 में खर्च किया जाना भी प्रत्याशित है । सरकार को आशा है कि यह योजना परिव्यय वर्ष के दौरान और भी बढ़ेगा ।

राज्य की अर्थ–व्यवस्था मुख्यतः कृषि, सिंचाई तथा बिजली पर आधारित है । औद्योनिक विकास का निर्भर बिजली के उत्पादन तथा वितरण पर है । अतः राज्य की अर्थ– व्यवस्था के विकास के लिए राज्य की वर्ष 1976–77 की वार्षिक योजना में सिंचाई और बिजली को परमाग्रता दी जाती रहेगी । यहां यह उल्लेख करना असंगत न होगा कि 563 करोड़ रुपए के पांचवें योजनागत परिव्यय में से 342 करोड रुपए सिंचाई और बिजली के लिए नियत किए गए हैं जो कुल योजना परिव्यय का 61 प्रतिशत है । (तालियां)

विकास कार्य

बिजली

11.00 बजे

कृषि तथा उद्योग के क्षेत्रों में विकास के लिए बिजली अत्यन्तावश्यक है । अतः राज्य सरकार ने वर्ष 197 6– 77 की वार्षिक योजना में बिजली परियोजनाओं को परमाग्रता दी है । राज्य के गांवों में शत प्रतिशत विद्युतन से सभी प्रकार के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 1968–69 में 4.06 लाख से बढ़कर 1974–7 5 में 7. 54 लाख हो गई है । बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 1968–69 में 69 यूनिटों के मुकाबले में 1974– 75 में बढ़कर 113 यूनिटें हो गई हैं । अधिक उपज वाले बीजों और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग होने के कारण पंपिंग सैट और नलकूप चलाने के लिए बिजली की मांग अत्याधिक बढ़ गई है । राज्य सरकार को गत कुछ वर्षों से बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है ।

बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने फरीदाबाद में 60 मैगावाट का पहला ताप बिजली घर लगाने का काम आरम्भ किया । यह बिजली–घर 1974–75 में चालू हो गया था और 60 मैगावाट का एक अन्य यूनिट अप्रैल, 1 976 में फरीदाबाद में चालू किया जाएगा । इस प्रकार वर्ष 1976–77 में कुल ताप क्षमता 204.30 मैगावाट हो जाएगी । फरीदाबाद ताप–घर में 60 मैगावाट का एक तीसरा यूनिट लगाने सम्बन्धी कार्यवाही की

जा रही है । राज्य में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए पानीपत में दो यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं जिनमें प्रत्येक की क्षमता 110 मैगावाट होगी । प्रसन्नता का विषय है कि पानीपत ताप–घर संयत्र पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है और' भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड से प्राय समस्त उपकरण प्राप्त हो चुके। हैं । गोबिन्द सागर में सामान्य माता में पानी आने के कारण, इस वर्ष के दौरान भाखडा से बिजली की सप्लाई की स्थिति सन्तोषजनक रही है । इसलिए अभी तक बिजली की सप्लाई पर कटौती लगाना आवश्यक नहीं समझा गया है । आशा है कि फरीदाबाद में 60 मैगावाट का दूसरा यूनिट चालू हो जाने से वर्ष 1976– 77 में बिजली की सप्लाई में निश्चित सुधार होगा ।

वर्ष 1976– 77 के दौरान बिजली परियोजनाओं में 52. 80 करोड़ रुपए की राशि लगाने का प्रस्ताव है । इसमें 20. 07 करोड़ रुपए की राशि बहु–उद्देशीय परियोजनाओं अर्थात् व्यास यूनिट ।, व्यास यूनिट 11 और व्यास पारेषण लाइनों(Beas Transmission) के लिए नियत की गई हैं और 32. 73 करोड़ रुपए की शेष राशि बिजली के उत्पादन, पारेषण (Transmission)और वितरण पर खर्च की जाएगी । वर्ष 1976–77 के दौरान 40,000 सामान्य कनैक्शनों और 1,000 उद्योग सेवा कनैक्शनों के अतिरिक्त 6,000 नलकूपों को भी बिजली दिए जाने का बजट में प्रस्ताव है । इस सम्बन्ध में सरकार ने वित्तीय संस्थाओं से विचार–विमर्श आरम्भ कर दिया है और आशा की

जाती है कि जिन नलकूपों के सम्बन्ध में टैस्ट रिपोर्ट मुकम्मिल हो चुकी है उन्हें बिजली देने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो जाएगा ।

सिंचाई

बिजली के बाद, सिचाई परियोजनाओं को परमाग्रता दी जा रही है । इन परियोजनाओं के निमित्त वर्ष 1976–7 7 के लिए 18.90 करोड़ रुपए की राशि नियत की गई है । यह राशि चालू परियोजनाओं तथा राज्य की अर्थ–व्यवस्था के विकास के लिए नितान्त आवश्यक समझी जाने वाली योजनाओं को पूरा करने पर खर्च की जाएगी । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों पर 54 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे । परिणामस्वरूप, राज्य में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र 1966– 67 में 32.75 लाख एकड़ से बढ़कर 1973–74 के अन्त तक 41 लाख एकड़ हो गया है ।

पांचवीं योजना की मुख्य तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिए 99.26 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं । यह राशि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर किए गए खर्च से 45.26 करोड़ रुपए अधिक है । पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी चालू मुख्य और मध्यम सिंचाई स्कीमे अर्थात् गुड़गांव नहर परियोजना, पश्चिमी यमुना नहर परियोजना, इंदिरा गांधी उठान सिंचाई स्कीम, बीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती

उठान–सिंचाई स्कीम, बीबीपुर झील की क्षमता बढ़ाने का कार्य., दिल्ली शाखा पुच्छ रजबाहे को पक्का करने का कार्य, मूनक नहर नियामक, हांसी शाखा को पक्का करने का कार्य, बुटाना और

सुन्दर उप–शाखा का सुधार और नया नियामक दादुपुर पूरे कर लिए जाएंगे । इन स्कीमों के अतिरिक्त पंडित जवाहर लाल नेहरू उठान सिंचाई स्कीम पर पूरे जोर से कार्य आरम्भ कर दिया गया है । इस स्कीम पर वर्ष 1975– 76 के अन्त तक कुल 8.83 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे । वर्ष 1975– 76 में जिला अम्बाला के घग्घर और टांगरी के बीच पड़ने वाले उच्चतलीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए नागल उठान सिंचाई स्कीम पर भी कार्य चालू किया गया है । रावी– ब्यास के फालतू पानी में हरियाणा राज्य के हिस्से के सम्बन्ध में भारत सरकार का अन्तिम निर्णय प्राप्त होने पर, सतलुज यमुना लिंक स्कीम का कार्य भी चालू कर दिया जाएगा । इस स्कीम पर 57 करोड़ रुपए खर्च होंगे । आशा है कि भारत सरकार के अन्तिम निर्णय की सूचना निकट भविष्य मैं प्राप्त हो जाएगी । इस अभिप्राय से हमने 1976–77 में हूल स्कीम के लिए 1 करोड़ रुपए का उपबन्ध किया है । हमारा प्रयास यह होगा कि 1976–77 में सतलुज यमुना लिंक स्कीम का खर्च बढ़ाया जाए ताकि निर्माण– कार्य यथाशीघ्र पूरे हो सकें और राज्य के किसान शीघ्रातिशीघ्र अतिरिक्त पानी का उपयोग कर सकें । पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान पंडित जवाहर लाल नेहरू उठान सिंचाई स्कीम, नागल उठान

सिंचाई स्कीम और सतलुज यमुना लिंक स्कीम भी पूरी हो जाएगी । वर्ष 1975– 76 के दौरान मुख्य और मध्यम सिंचाई स्कीमों पर 17. 85 करोड़ रुपए खर्च होने की सम्भावना है । इस राशि में सूखा राहत कार्यों पर होने वाला 38 लाख रुपए का खर्च भी सम्मिलित है । इस सम्बन्ध में वर्ष 1976–77 की मुख्य और मध्यग्र सिंचाई स्कीमों की योजनागत अधिकतम सीमा 16.10 करोड़ रुपए नियत की गई है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र बढ़कर 45 लाख एकड़ (18 लाख हैक्टेयर) हो जाने की सम्भावना है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इन्दिरा गांधी उठान सिंचाई स्कीम, बीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती उठान सिंचाई स्कीम, पंडित जवाहर लाल नेहरू उठान सिंचाई स्कीम आदि उठान सिंचाई स्कीमें हमारे राज्य के दक्षिण–पश्चिमी भागों में स्थित क्षेत्रो को सिंचाई–सुविधाएं देंगी ताकि इन क्षेत्रो को बार बार पड़ने वाले अकालों से राहत मिल सके । इससे राज्य में क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने तथा कृषि के उत्पादन सें स्थिरता लाने में भी सहायता मिलेगी ।

कृषि उत्पादन

राज्य की अर्थ–व्यवस्था अभी भी कृषि प्रधान है और इसलिए 1976– 77 में 49.25 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के पूरे प्रयत्न किए जाएगे । वर्ष 1976– 77

के दौरान कृषि तपा सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए 12.94 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त, 1 97 6– 77 के दौरान इस क्षेत्र में 5. 39 करोड रुपए की केन्द्र चालित स्कीमों को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव भी है ।

वर्ष 1975– 76 के दौरान 46.60 लाख टन का कुल खाद्य उत्पादन होने की सम्भावना– है और आशा है कि राज्य का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जाएगा । गेहूं और चने के बढ़िया बीजों और चने के लिए राईजोबियम कल्चर (Rhyzobium Cultures) के वितरण तथा कृषकों को कृषि के विभिन्न तरीकों के बारे में पैकेज प्रशिक्षण देने हेतु अत्यधिक प्रयत्न किए गए हैं । कृषकों को रासायनिक उर्वरकों का उचित प्रयोग सिखाने के लिए भूमि परीक्षण अभियान चलाए गये हैं । अधिक उत्पादन की उड़ेश्यपूर्ति हेतु बड़े पैमाने के सम्पर्क कार्यक्रमों, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्मों तथा किसान मेलों की व्यवस्था की गई है । अधिक उत्पादन वाली फसलें बोने का प्रचलन अब अदिक हो गया है तथा 1974– 75 में 14.48 लाख हैक्टेयर भूमि के मुकाबले में 1975– 76 के दौरान 14. 86 लाख हेक्टेयर भूमि में अधिक उत्पादन वाले बीजों का प्रयोग किया गया ।

राज्य ने, वर्ष 1976– 77 के लिए 49.25 लाख टन का खाद्यान्न उत्पादन गुड के रूप में 7.50 लाख ईख के उत्पादन, 1. 20 लाख टन तिलहन और 4.50 लाख कपास की गांठों के उत्पादन के ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए हैं । चावल का उत्पादन

और उसके अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाने तथा बाजरे का प्रति हैक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के निमित्त खरीफ 1976 के दौरान अधिक बल दिया गया । ये फसलें राज्य की खरीफ की मुख्य फसलें हैं ।

वर्तमान संकर बाजरा– 3 किस्म के स्थान पर नई रोग प्रतिरोधी पी ० एच० बी ० – 14 बोया जाना अभिप्रेत है । धान और गेहूं का उत्पादन और बडाने हेतु अधिक उत्पादन वाली फसलों के प्रमाणित उच्च जनन बीजों के विक्रय में वृद्धि करने का विचार है ताकि किसान अपने बीजों का प्रतिस्थापन करू सकें ।

वर्ष 1976– 77 के दौरान अधिक उत्पादन वाली किस्मों का लक्ष्य 15.70 लाख हैक्टेयर रखा गया है । रासायनिक उर्वरक की खपत की 1975–76 की सम्भावित उप– लब्धि 94,746 टन होगी । इसके विरुद्ध आगामी वर्ष में तत्सम्बन्धी लक्ष्य 1.15 लाख टन का निर्धारित किया गया है । भुमि तथा जल प्रबन्ध साधनों के निश्र वर्ष 1975–76 के दौरान 18,000 हैक्टेयर की संभाव्य उपलब्धि के मुकाबले में 23,000 हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है । इसी प्रकार भूमिगत जल साधनों को और अधिक विकसित करने का प्रस्ताव है तथा 1978– 77 के दौरान लघु सिंचाई के सम्बन्ध में 2,15,000 यूनिटों की उपलब्धि संभावित है । कृषकों को उथले नलकूपों, छिड़काव सिंचाई, जल प्रबन्ध, भूमि विकास, भूमि उद्धार और ट्रैक्टरों आदि के लिए ऋण देने हेतु विश्व बैक, ए० आर० सी० तथा अन्य व्यापारिक बैंकों से 21.85 करोड़ रुपए के सांस्थानिक वित्त जुटाए जाएंगे । एक ओर तो कृषि उत्पादन

बढ़ाने और दूसरी ओर कृषकों को ईंधन उपलब्ध कराने के अभिप्राय से खाद के अधिरक्षण के लिए राज्य में गोबर गैस सं–बल सम्बन्धी क्रैश कार्यक्रम आरम्भ किया गया है । आशा की जाती है कि हम 31 मार्च, 1976 तक 1 2,000 गोबर गैस संयतों को लगाने के लक्ष्य को काफी हद तक पूरा कर सकेंगे (तालियां) और वर्ष 1976– 77 के दौरान, इनकी संख्या 14,000 तक हो जाने की सम्भावना है । कृषि कार्यक्रमों में पौधा सुरक्षा को परमाग्रता दी जाती रहेगी । वर्ष 197 6– 77 के दौरान फसलों के रोगों और उन्हें लगने वाले कीडे–मकौडों से खाद्य फसलों के 26 लाख हैक्टेयर और व्यापारिक फसलों के 12 लाख हैक्टेयर की बचाव सम्बन्धी स्कीमें विचाराधीन हैं । 1 97 6– 77 में हुक लाख हैक्टेयर भूमि में वायुयानों द्वारा छिड़काव करने का लक्ष्य है, जबकि वर्ष 1975– 76 में 40,000 हैक्टेयर में छिड़काव होने की संभावना है । वर्ष 197 4–75 सम्बन्धी वास्तविक आंकड़े 22,000 हैक्टेयर थे । माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वायुयानों द्वारा छिड़काव के लिए कृषि–वायुयान प्राप्त करने में हरियाणा राज्य मार्ग–दर्शन राज्यों में से हुक है (तालियां) । हिसार कृषि विश्वविद्यालय अनुसंधान कार्यों की तरफ विशेष ध्यान दे रहा है रू । अधिक उर्वरता के लिए डब्ल्यू ० एच० 147 गेहूं, जो नया तथा छोटे तनों वाला है, विश्व विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है और उसकी किस्म का कृषकों के खेतों में परीक्षण किया जा रहा है । जहां तक तिलहन का सम्बन्ध है नई किस्म का राया आर० एच०– 29 और तोरिया सिंथेटिक– 65 आम काश्त के

लिए जारी कर दिए गए हैं । दालों में माश 70– 3 किस्म विषाणु रोग के त्निए अधिक प्रतिरोधी पाई गई है । और प्राय रू थोड़े दिनों में अधिक उपज देती है । गन्ने में पकने वाली सी० ओ० – 6914 और देर से पकने वाली सी० ओ० एच०– 1 किस्में जारी किए जाने के लिए तैयार हैं । टमाटरों की दो किस्में एच० एस०– 101 और एच० एस० – 102 जारी की गई हैं ।

विभिन्न नस्लों के पशुओं को होने वाले विभिन्न रोगों सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है । विश्वविद्यालय के अनुसंधान फार्मों और प्रयोगशालाओं में क्षेत्रीय समस्याओं की छानबीन की जा रही है । ये फार्म और प्रयोगशालाएं राज्य के विभिन्न कृषि–जलवायु वाले क्षेत्रो में फैली हुई हैं । राज्य के सभी (ग्यारह) जिला–मुख्या– लयों में कृषक परामर्श सेवा केन्द्रों (कृषि ज्ञान केन्द्रों) की स्थापना की गई है ।

पशु पालन

पशुपालन एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिसके विकास से राज्य के अनेक लोग विशेषकर छोटे और सीमान्त. कृषक और भूमिहीन श्रमिक समृद्ध होंगे । अतः 1975– 76 में 49.05 लाख रुपए के मुकाबले में 1976– 77 के लिए 81. 70 लाख रुपए की राशि नियत की गई है । इसके अतिरिक्त 1976– 77 के दौरान कुल मिलाकर 115. 61 लाख रुपए की लागत से केन्द्र चालित–सहायता प्राप्त स्कीमों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है,

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, करनाल, गुड़गांव। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, भिवानी और जींद नामक छः जिलों में क्रमबद्ध नस्ल सुधार कार्य, जो सघन पशु विकास परियोजना के नाम से जाना जाता है, चालू किया गया था । नए बने सिरसा जिले में ऐसी एक अन्य परियोजना की स्थापना की जा रही है । वर्ष 1978–77 के दौरान इस परियोजना में एक वीर्य बैक खोला गया है, जिसमें एक क्षेत्रीय कृत्रिम सेचन केन्द्र और 15 पशुपालन केन्द्र शामिल होंगे ।

1976–77 में कम दूध देने वाली स्वदेशी गायों को जरसी और हालस्टियन फरी– जियन नस्ल के अधिक द्ध देने वाले विदेशी सांडों से संकरित करने पर विशेष बल दिया जाएगा । अभिप्राय यह है कि दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक विशेष नस्ल का विकास किया जा सके । हिसार में भारतीय आस्ट्रेलियन पशु परियोजना और डेनमार्क की सरकार की सहायता से गुड़गांव में फ्रोजन सीमन बैक भी संकरण कार्यक्रम की सहायता के 'लिए उपलब्ध हो गए हैं । उत्तम नस्ल के सांड तैयार करने के लिए, राजकीय पशुधन फार्म, हिसार में मुराह भैसों की संख्या में वृद्धि करने के साथ साथ अधिक प्रजनक नस्ल के बढ़िया मुराह सांडों से मुराह नस्ल की भैसों के मेल से नस्ल को सुधारने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

मुर्गीपालन विकास कार्यक्रमों में पर्याप्त सफलता मिली है, जिसके परिणामस्वरूप मुर्गियों की संख्या लगभग दुगुनी हो गई है । इसके अतिरिक्त एस. एफ. डी. ए.–एम. एफ. ए. एल. एजेंसी

अम्बाला के अधीन लाभ पाने वालों को सप्लाई करने के लिए अम्बाला के मुर्गीपालन फार्म में 8,000 अण्डा देने वाली मुर्गीयों के पोषण का प्रस्ताव है ।

मांस और बढ़िया ऊन का उत्पादन बढ़ाने के विचार से भेड़ों की अधिक संख्या की प्रजनन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भेड़ तथा ऊन विस्तार केन्द्रों को अपेक्षित इन्पुट सहित 200 बढ़िया नस्ल के मेंढे भी सप्लाई किए जाएंगे । 1975– 78 के लिए भेड़ प्रजनकों से ऊन खरीदने के लिए योजनेतर बजट में 20 लाख रुपए का उपबन्ध किया गया है और 1978– 77 में भी इस प्रयोजन के लिए ऊन ग्रेडिंग परियोजना, लोहारू के द्वारा 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे ।

पशु प्लेग और मुंह–खुर बीमारियों के उन्मूलन सम्बन्धी कार्यक्रमों के अतिरिक्त वर्ष 197 8–? 7 में स्वास्थ्य संगठन को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावशाली पग उठाए जाएंगे । इस सम्बन्ध में इस समय 175 पशु चिकित्सा अस्पताल, 138 डिस्पैसरिया तथा 3 चल पशु चिकित्सा क्लीनिक हें । आगामी वर्ष में 20 पशु चिकित्सा डिसपैंसरियों की वृद्धि की जाएगी और 20 डिस्पैसरियों का दर्जा बढ़ा कर अस्पताल बना दिया जाएगा और तीन चल क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे । इसके अतिरिक्त, अम्बाला, करनाल, गुड़गांव, भिवानी और हिसार के चुनीदा जिलों में दोगली बछडी पालन, मुर्गी– पालन, सूअर पालन और भेड पालन के लिए केन्द्र चालित सहायता प्राप्त कार्यक्रम को प्रारम्भ करना एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष

है । इस कार्यक्रम को छोटे और सीमान्त किसानों भूमिहीन श्रमिकों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा । इस परियोजना का उद्देश्य पांचवी पंचवर्षीय योजना के शेष तीन वर्षों के दौरान 20,000 दोगली बछडियां पालने के लिए संतुलित चारे की व्यवस्था करना है और इस पर होने वाला खर्च भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 2:1 के अनुपात में वहन किया जाएगा । इसी प्रकार, मुर्गी–पालन–उत्पादन में 9,000 परिवार, सूअरपालन में 500 परिवार और भेड–उत्पादन में 6,000 परिवार कार्यरत होंगे और इन यूनिटों की स्थापना के लिए पूंजी निवेश पर छोटे किसानों को 25 प्रतिशत की दर से और सीमान्त किसानों एवं भूमिहीन श्रमिकों को 3313 प्रतिशत की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी' । शेष निधियों की व्यवस्था सांस्थानिक स्रोतों से मध्यमावधि कर्जों के रूप में की जाएंगी । डेरो विकास हरियाणा डेरी विकास निगम की स्थापना जनवरी, 1970 में की गई थी । इस निगम की स्थापना के पश्चात् चार वर्षों की बहुत ही कम अवधि में जींद, भिवानी और अम्बाला में तीन दुग्ध प्लांट चालू किए गए । आप्रेशन फलड(operationflood) कार्यक्रम के अधीन रोहतक में एक अन्य दुग्ध प्लांट मुकम्मिल होने वाला है और आशा है कि इसी वित्त वर्ष में यह प्लांट चालू हो जाएगा । अब तक के बने दुग्ध प्लांटों में यह सब से बड़ा होगा और इसकी दैनिक क्षमता एक लाख लिटर दूध होगी । दो अन्य प्लांटों का निर्माण कार्य काफी हद तक पूरा हो चुका हए । ये

दुग्ध प्लांट हिसार तथा फरीदाबाद के स्थानों पर लगाए जा रहे हैं ।

वर्ष 1975–76 के क्रार्यक्रम पर 94.50 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं । इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 27.35 लाख रुपयों का उपबन्ध किया जाना है और शेष राशि वित्तीय संस्थाओं के ऋण के रूप में ली जाएगी । सूखा ग्रस्त क्षेत्र–सहायता कार्य–क्रम के अन्तर्गत नारनौल में एक अवशीतन केन्द्र (Chilling Centre) भी स्थापित किया जा रहा है । आशा है किं यह परियोजना वर्ष 1976–77 में पूर्ण हो जाएगी ।

वर्ष 1976– 77 में चालू परियोजनाओं को मुकम्मिल करने के लिए 116 लाख रुपए का परिव्यय अपेक्षित होगा । इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार 40 लाख रुपए का उपबन्ध करेगी और शेष राशि सांस्थानिक खोतों से ऋण के रूप में ली जाएगी ।

सहकारिता

हरियाणा की कृषि प्रधान अर्थ–व्यवस्था में 'हरित क्रान्ति, को बढ़ावा देने के लिए सहकारी ऋण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । माननीय सदस्यों को यह सूचना देते हुए यह मुझे प्रसन्ता अनुभव होती है कि 1966– 67 से सहकारी ऋण पांच गुणा से भी अधिक हो गया है । सभी प्रकार की समितियों में कुल सदस्यों की संख्या 9.23 लाख से बढ़कर 19 74–75 में 14.81

लाख हो गई है । इनकी कार्यकर पूंजी वर्ष 1960– 67 में 58.90 करोड़ रुपए थी वह वर्ष 1974– 75 में बढ़कर 306. 48 करोड़ रुपए हो गई है । इस प्रकार कार्यकर पूंजी पिछले आठ वर्षों में 247.58 करोड़ रुपए बढ़ी है । लगभग 47.7 प्रतिशत ग्रामीण जनसंरव्या के लिए इस समय 6, 565 कृषि उधार समितियां हैं । इन समितियों ने वर्ष 1974–75 में 37.19 करोड़ रुपए के लघु अवधि एवं मध्य अवधि ऋण दिए, जबकि वर्ष 1966–67 में केवल 8 करोड़ रुपए के ही ऋण दिए गए थे । अब सरकार कमजोर समितियों को आर्थिक रूप से सक्षम यूनिट बनाने के लिए उन्हें बड़े बहु उद्देशीय यूनिटों में मिलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है । नलकूप लगाने, ट्रैक्टर खरीदने, भूमि समतल करने आदि के लिए वर्ष 1 974–75 में 29 प्राथमिक भू–बन्धक बैंकों के माध्यम से 13.52 करोड़ रुपए के दीर्घ अवधि के ऋणों की व्यवस्था की गई ।

जहां तक विपणन का सम्बन्ध हए, हरियाणा राज्य सहकारी सप्लाई तथा विपणन संघ 72 विपणन समितियों की शिखर संस्था है । इस संघ की कार्य संचालन राशि वर्ष 1974– 75 ने बढ़कर 15.87 करोड़ रुपए हो गई, जबकि वर्ष 1966– 67 में यह राशि 5.54 लाख रुपए थी । रबी, 1975 के दौरान संघ ने 14.29 करोड़ रुपए की कीमत की 1. 1 2 लाख टन गेहं की अधिप्राप्ति की । वर्ष 197 4–7 5 में रासायनिक उर्वरकों की 20.06 करोड़ रुपए की बिक्री हुई । इस संघ द्वारा तरावडी में एक

दानेदार रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक प्लांट, भिवानी में एक बेकरी, अम्बाला तथा हिसार में दाल मिलें और विभिन्न स्थानों पर चावल मिले स्थापित की गई । अब संघ द्वारा हांसी में 5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की एक कताई मिल की स्थापना की जा रही है ।

जहां तक चीनी उद्योग का सम्बन्ध है, पानीपत और रोहतक में स्थित दो सहकारी चीनी मिलें लाभ में चल रही हैं । इन मिलों में वर्ष 1974–75 में 43. 64 लाख क्विटल गन्ना पीड़ा गया और 431 लाख क्विटल चीनी तैयार की गई । पानीपत चीनी मिल में आसवनी यूनिट (Dikstillery Unit) की स्थापना भी की जा चुकी है । करनाल और सोनीपत में 11.35 करोड़ रुपए की कुल लागत की दो अन्य सहकारी मिलें निर्माणाधीन हैं । इन मिलों में लगभग 1976 के अन्त तक काम आरम्भ हो जाएगा । वर्ष 1976–77 के दौरान सरकार का विचार दो अन्य सहकारी चीनी मिलें भी चालू करने का है ।

जहां तक डेरी–फार्मिग का सम्बन्ध है, 976 सहकारी समितियां डेरी विकास निगम द्वारा अम्बाला, जींद और भिवानी में स्थापित दुग्ध प्लाटों को दूध सप्लाई करती रही हैं । सहकारिता शीर्ष के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यक्रमों. के लिए राज्य सरकार द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 9.80 करोड़ रुपए खर्च किए जाने निश्चित किएगए हैं । इस राशि में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाले 4.80 करोड़ रुपए भी शामिल हैं ।

बन तथा वन्य जीव

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानों में 20 प्रतिशत क्षेत्र में और पहाड़ी इलाके में 60 प्रतिशत क्षेत्र में वन लगाने का नार्म (norm) निश्चित हद, परन्तु इसके विरुद्ध हरियाणा में वनों के अधीन क्षेत्र बहुत कम है । इसलिए हमारे पास इस के इलावा कोई और चारा नहीं है कि ऐसे सभी स्थानों पर जहां पौधे लगाए जा सकते हैं, लगाएं । ऐसे स्थान, सड़कें, नहरें, रेलवे–लाईनों के साथ–साथ वाली भूमि, सरकारी भूमि, मरुस्थल और पहाड़ी क्षेत्र हैं । वृक्षारोपण और भू–संरक्षण से, विशेष रूप से राजस्थान के साथ लगते क्षेत्र में न केवल कृषि उत्पादन में स्थिरता आएगी बल्कि इन उपायों से इस राज्य के राजस्थान के साथ लगने वाले जिलों में राजस्थान की तरफ से बढ़ रहे मरुस्थल की भी रोकथाम हो सकेगी । वन–सोतों के सुधार और वन्य जीवन के विकास के निमित्त वन विभाग के लिए वर्ष 1976– 77 के दौरान 39. 40 लाख रुपए नियत किए गए हैं ।

सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में 15 नवम्वर, 1975 तक सभी वन्य पशुओं और वन्य पक्षियों के शिकार पर रोक लगा दी गई थी (तालियां) । यह निर्णय भगवान महावीर, जिनका 2500वां 'निर्वाण वर्ष' इस वर्ष मनाया गया है, के उच्च आदर्श 'अहिंसा परमो धर्म' को ध्यान में रखकर लिया गया था । (तालियां)

मछली पालन

अनुमान है कि मछली पालन के लिए उपयुक्त जलाशय लगभग 1,200 हैक्टेयर क्षेत्र में हैं । उत्तम किस्म के मछली–पोना अधिप्राप्त किए जाने और मछली पालन के लिए तालाबों के सुधार किए जाने पर बल दिया जाता रहा है । हरियाणा राज्य में सात मछली– पोना फार्म हैए ।

पंचवर्षीय योजना में उत्तम किस्म के मछली –पोना के पर्याप्त माता में उत्पादन और उपेक्षित तालाबों का सुधार किए जाने पर बल दिया जाता रहेगा । वर्ष 1978–77 के दौरान लगभग 15, 500 क्विटल मछली का उत्पादन किया जाएगा । वर्ष 1976–77 की योजना स्कीमों के लिए 8. 50 लाख रुपए की राशि का अनुमोदन किया गया है ।

सड़कें

सडकें अर्थ–व्यवस्था के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे कृथि और उद्योग को बढ़ावा देने तथा अकाल और बाढ़ जैसी आपाताकि स्थितियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं । सन्तोष का विषय है कि राज्य में पक्की सड्कों की कुल लम्बाई वर्ष 1968–69 में 6,012 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 1974– 75 में 14,280 किलोमीटर हो गई तथा इसी अवधि के दौरान पक्की सड़कों से जोड़े गए गांवों की संख्या 1,742 से बढकर 4,360 हो गई । आशा है कि इस वित्त वर्ष के अन्त तक 500 किलोमीटर लम्बी और सड़कें पक्की की जाएंगी

तथा राज्य के 250 और गांव सड्कों से जोड़ दिए जाएंगे । चालू वित्त वर्ष के दौरान 1,500 रुलिया पूरी हो जाने की आशा है । यह भी आशा की जाती है कि इस अवधि के दौरान 4,000 किलोमीटर सड़कों पर डामर बिछाई (sufrace dressing) की जाएगी ।

योजना शीर्ष के अधीन वर्ष 1975– 78 के दौरान सड़कों पर 4 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी । इसमे न्यूनतम–आवश्यकता कार्यक्रम पर होने वाले 50 लाख रुपए की राशि भी शामिल है । आगामी वित्त वर्ष 1976– 77 में 3.30 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है । इसमें न्यूनतम–आवश्यकता–कार्यक्रम पर खर्च होने वाले 70 लाख रुपए की राशि सम्मिलित है ।

सड़क परिवहन

राज्य परिवहन विभाग, 'हरियाणा राज्य परिवहन' नामक अत्यन्त प्रभावी उपक्रम के माध्यम से वालियों में लोकप्रियता और विश्वसनीयता प्राप्त कर रहा है (तालियां) । यह अपनी नियमित तथा आरामदेह सेवाओं के लिए भी प्रख्यात है । इसके पास कुल 1,710 बसें हैं । वर्ष 1976–77 के दौरान 200 नई बसों की वृद्धि की जाएगी और इसी वर्ष में 189 पुरानी बसों को बदल दिया जाएगा । 'हरियाणा परिवहन' की बसें प्रतिदिन 4. 42 लाख यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा लगभग 4 लाख

किलोमीटर का फासला तय करती हैं । विभाग ने अब पूर्णत रू धातु की बनी बसों का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया है, जोकि कम्पोजिट टाईप की बसों की अपेक्षा अधिक मजबूत होती हैं । नई सिटी टाईप बढ़िया बसें भी चला दी गई हैं । लम्बा रास्ता तय करने वाले यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राज– स्थान और हिमाचल प्रदेश से अन्तर्राज्य पारस्परिक अनुबन्ध किए गए हैं । चण्डीगढ– दिल्ली मार्ग पर एक नई वातानुकूलित बस भी चलाई गई है । यात्रा के समय को लगभग 25 प्रतिशत कम करने के लिए विभिन्न मार्गों पर एक्सप्रैस बसें चला दी गई हैं । अत्यधिक यातायात तथा मेलों के अवसरों पर विशेष बसें चलाई जाती हैं । यातायात की आवश्यक– ताओ को सुचारू तथा किफायती ढंग से पूरा करने के लिए हरियाणा परिवहन का पुनर्गठन किया जा रहा है । चालू वर्ष में 3.15 करोड़ रुपए की राशि के मुकाबले में वर्ष 1976–77 के लिए 5.59 करोड़ रुपए की राशि नियत की गई है ।

वर्ष 1976– 77 में यातायात के विभिन्न महत्वपूर्ण जंक्शनों पर लगभग 30 बस–क्यू शैल्टर्ज (Bus Queue Shelters) बनाए जाएंगे । भिवानी, कैथल तथा जींद में नए वर्कशाप–भवन निर्माणाधीन हैं । इन वर्कशापों के वर्ष 1976– 77 में पूरा हो जाने की सम्भावना है । नारनौल के बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य वर्ष 1976–77 में पूरा हो जाएगा । हांसी का बस–अड्डा भी प्रयोग के

लिए खोल दिया जाने की संभावना है तथा सोनीपत में बस–अडा बनाने का कार्य भी आगामी वर्ष में आरम्भ किया जाएगा ।

उद्योग

विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद राज्य में उद्योग की प्रगति लगातार होती रही । लघु' उद्योग यूनिटों की संख्या जून, 1 975 तक 1 6, 700 हो गई, जबकि 1966– 67 में यह संख्या 4, 589 थी । चालू वर्ष के दौरान जून, 1975 के अन्त तक 572 यूनिटों का पंजीकरण किया गया था । बड़े तथा मध्यम पैमाने के क्षेत्र में, भारत सरकार ने 61 औद्योगिक लाइसेंस तथा 38 आशय–पत्र जारी किए हैं । इस प्रकार आशय–पलों और औद्योगिक–लाइसेंसों की कुल संख्या क्रमशः 270 और 492 हो गई है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने चालू वर्ष के दौरान विभिन्न मद्दों के निर्माण हेतु 2० यूनिटों को सी० ओ० बी० लाइसेंस भी दिए. हैं । इन यूनिटों में कुल 7 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे तथा इनसे लगभग 1,000 व्यक्तियों को रोजगार देने की क्षमता होगी ।

चालू वर्ष के दौरान दो संयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं, नामतः हरियाणा पालीस्टील लिमिटिड, हिसार तथा हरियाणा टैलीविजन, फरीदाबाद, में उत्पादन आरम्भ हो चुका है । इसके अतिरिक्त, हरियाणा राज्य उद्योग विकास निगम शीशे की बोतलें, सिंथेटिक डेटरजेंट, कास्टिक सोडा, हाथ–औजार आदि अन्य विभिन्न परियोजनाएं स्थापित कर रहा है । चालू वर्ष में भारत

सरकार ने गैर–सरकारी क्षेत्र में मुर्थल मैं स्कूटर परियोजना, रोहतक तथा सोनीपत मैं दो शीट ग्लास यूनिट लगाने की स्वीकृति दे दी है जिन पर 7.26 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी तथा इनसे लगभग 3,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा । आशा है कि ये परियोजनाएं 1976–77 के दौरान चालू हो जाएंगी ।

राष्ट्रीय रासायनिक उर्वरक लिमिटिड (भारत सरकार उपक्रम) एक रासायनिक उर्वरक परियोजना पानीपत में स्थापित कर रही है जिस पर कुल पूंजीगत परिव्यय लगभग 130 करोड़ रुपए होगा जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी शामिल है (तालियां) । इस परियोजना के लिए 442 एकड़ भूमि का अभिग्रहण किया गया है ।

हरियाणा वित्त निगम ने वर्ष 1974–75 के दौरान 336 औद्योगिक इकाइयों के लिए 9.27 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जबकि गत वर्ष 316 इकाइयो के लिए 6.43 करोड़ रुपए स्वीकृत कितु गए थे । निगम के कार्य की एक खास बात यह रही कि निगम द्वारा अब तक 28 प्रतिशत निवेश राज्य के पिछड़े क्षेत्रो में किया गया है ।

हरियाणा राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम जिला गुड़गांव मैं निर्यात विधायन क्षेत्र (Export Procekssing Zone) स्थापित कर रहा है जो व्यापार विकास प्राधिकरण के सहयोग से निर्यात करने के लिए ही पोशाकें तैयार करेगा । इस प्रयोजन के

लिए वर्ष 1975–76 में उनको 15 लाख. रुपया दिया जाने का प्रस्ताव है । 1967– 68 में औद्योगिक सामान का निर्यात 4.50 करोड़ से बनकर 1974– 75 में 35 करोड़ रुपए हो गया है ।

ऐसे इलाकों में, जो, राज्य द्वारा पिछड़े घोषित किए गार हैं, औद्योगिक इकाइयों में लगाए गए पूंजीगत निवेश के लिए 15 प्रतिशत अनुदान देने की केन्द्रीय सरकार की स्कीम को निष्पादित किया जा चुका है । वर्ष 1974– 75 के दौरान राज्य मैं 45 औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक सहायता के रूप में कुल 21. 25 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं और चालु वर्ष में इस प्रयोजन के लिए 30 लाख रुपए विनियत किए गए हैं और वर्ष 1976–77 के दौरान 20 लाख रुपए का उपबन्ध किया गया है । विभाग अब तक शिक्षित बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने, बीज–धन तथा अन्य सुविधाएं जुटाने के लिए 1.10 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है और राज्य में इस स्कीम के प्रारम्भ होने के पश्चात् शिक्षित बेरोजगार योजना के अन्तर्गत 80 परियोजनाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं ।

नगर तथा ग्राम आयोजना

समस्त हरियाणा राज्य में नगरों तथा मण्डियों के शहरी तया प्रादेशिक आयोजन एवं विकास– को उचित महत्व दिया जा रहा है । नगर तथा ग्राम आयोजन विभाग ने "Panjab Scheduled Road and Controlled Area REstruictions on Unregulated Development Act] 1963" के अन्तर्गत 23 स्थानों पर शहरी केन्द्रों के इर्द–गिर्द सम्भावी क्षेल घोषित किया है और 19 नियलित क्षेत्रो

के सम्बन्ध में विकास योजनाए प्रकाशित की हैं । भिवानी, पलवल, रिवाडी तथा नारनौल के इर्द–गिर्द नियंत्रित क्षेत्रो की विकास योजना तैयार की जा रही है । राज्य में सभी महत्वपूर्ण नगरों की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय निकाय तथा जिला प्रशासन के परामर्श से 25 नगरों के लिए अन्तरिम मास्टर योजनाएं तैयार की गई हैं । ये मास्टर योजनाएं इन योजनाओं में निर्दिष्ट भू–प्रयोजनों के अनुरूप इन नगरों के विकास का मार्ग–दर्शन करती हैं । इन मास्टर योजनाओं का अनुपालन स्थानीय निकायों सहित सभी सम्बद्ध विभागो द्वारा किया जाता है ।

हरियाणा राज्य से सम्बन्धित राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रो की उप–क्षेलीय योजनाएं तैयार की जा चु की हैं और आवास पद्धति तथा परिवहन सुविधाओं के विस्तार सम्बन्ध प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गए हैं ।

इसके अतिरिक्त नगर तथा ग्राम आयोजन विभाग, ग्राम विकास बोर्ड की सहायता कर रहा है जिससे कि वह माडल तथा फोकल गांवों का विकास कर सके । मंढौर (अम्बाला) । आजाद नगर (रोहतक), फिरोजपुर नमक (गुड़गांव) । खानक (भिवानी) तथा आर्जाहेडी (करनाल) जैसे माडल ग्रामों का विकास कार्य विकास योजनाओं के अनुसार आरम्भ किया गया है । नगर सम्पदा विभाग द्वारा विभिन्न नगर सम्पदाओं में रिहायशी, व्यापारिक तथा औद्योगिक प्लाटों का अभिग्रहण विकास तथा त्रय किया जाना प्रस्ताविक है । ये सम्पदाएं धारूहेडा, रिवाडी,

पंचकूला, कुरुक्षेत्र आदि में स्थापित की जा रही हैं । आवास हरियाणा आवास बोर्ड राज्य में लोगों की बत्ती हुई आवास सम्बन्धी जरुरतों को पूरा करने के लिए प्रशंसनीय कार्य कर रहा है । निधियों की कमी तथा भवन–निर्माण– सामग्री उपलब्ध न होने के बावजूद आवास बोर्ड मार्च, 1975 के अन्त तक 1,978 मकानों का निर्माण पूरा कर चुका है और आशा की जाती है कि बोर्ड चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक लगभग 1, 955 और मकानों का निर्माण कर लेगा । यह प्रत्याशित है कि वर्ष 1976– 77 में आवास बोर्ड लगभग 2,000 मकानों का निर्माण कर सकेगा । 18,000 रुपए तक की वार्षिक आय के वर्गों में आने वाले व्यक्तियों को मकानों के निर्माण में वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य में निम्न आय वर्ग आवास स्कीम तथा मध्यम आय वर्ग आवास स्कीम नामक दो स्कीमें कार्यन्वित की जा रही हैं । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन स्कीमों के लिए 43 लाख रुपए की रकम का उपबन्ध किया गया है । 1976–77 के बजट अनुमानों में इस प्रयोजन के लिए 40 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है ।

सरकारी कर्मचारियों को भवन–निर्माण ऋण के रूप में वर्ष 197 4– 75 में 70 लाख रुपए की रकम दी गई और चालू वित्त वर्ष में 75 लाख रुपए की रकम दिए जाने की सम्भावना है । आगामी वित्त वर्ष (1978– 77) में 80 लाख रुपए की रकम का उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है ।

सरकारी आवास भवनों के निर्माण के लिए वर्ष 1974–75 के दौरान 33 लाख रुपए की रकम का उपबन्ध किया गया था । चालू वित्त वर्ष के दौरान 41 लाख रुपए की रकम खर्च किए जाने की सम्भावना है । वर्ष 197 6– 77 के लिए 25 लाख रुपए की रकम का उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पुलिस आवास के लिए 31 लाख रुपए का तथा बजट अनुमान 1976– 77 में 15 लाख रुपए का उपबन्ध किया है ।

अवमानवीय परिस्थितियों में रह रहे गन्दी बस्तियों के निवासियों के माहौल में सुधार लाने के लिए वर्ष 1975– 76 के दौरान अम्बाला तथा भिवानी के नगरों में एक लाख रुपए की रकम खर्च की जाने की सम्भावना है । इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1976–77 के दौरान 5 लाख रुपए की रकम का उपबन्ध किया जाना प्रस्तावित है ।

देहाती क्षेत्रों में भूमिहीन कामगारों को विकसित गुह–स्थान जुटाने के लिए वर्ष 1974–75 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत एकु लाख रुपए. की रकम खर्च की गई तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान एक लाख रुपए और खर्च किए जाने की सम्भावना है । इस स्कीम के महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्ष' 1976– 77 में 6 लाख रुपए का उपबन्ध किए जाने का प्रस्ताव है ।

पर्यटन

चौथी पंचवर्षीय योजना काल में पर्यटन विभाग ने अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रगति की है जिसके फलस्वरूप हरियाणा राज्य भारत के पर्यटन–मानचित्र में स्थान पा गया है । (तालियां) राज्य से नजरने वाले सभी राज–मार्गों पर अथवा उनके निकट स्थानों पर सुसज्जित पर्यटक बगलों–कुटीरों–मोटलों, शिविर स्थलों, रेस्तराओं इत्यादि सहित बहुत से पर्यटन काम्पलैक्स स्थापित किए गए हैं । ये काम्पलैक्स समालखा, घरौंडा (केवल मिल्क बार) । चक्रवर्ती झील, पिपली, पंचकूला, यादवेन्द्र गार्डन पिंजौर, फरीदाबाद, बडखल झील, सूरजकुण्ड, धारूहेडा, होडल, सुलतानपुर झील, सोहना में हैं । इसके अतिरिक्त भिवानी, नारनौल, हिसार, जींद । रोहतक, सोनीपत और गुड़गांव में एक–एक रेस्तरां भी खोला गया है । हिसार में एक बेकरी भी है । इस अवधि के दौरान इन पर 2.07 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन पर अनन्तिम रूप से 3 करोड़ रुपए का परिव्यय निश्चित किया गया है । इसमें से पांचवी योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 1974– 75 के दौरान मौजूदा पर्यटन काम्पलैक्सों के और विस्तार के लिए 92.37 लाख रुपए खर्च किए गए । वर्ष 1975– 76 के लिए जो कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना का दूसरा वर्ष है और इस समय चल रहा है 63 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है और पर्यटन को और विकसित करने का कार्य सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है । बडखल झील पर सोना तथा स्टीमबाथ की सुविधाओं वाला एक

अत्याधुनिक तैरने का तालाब, सूरजकुंड में सुसज्जित पर्यटन बंगला तथा शिविर स्थल, समालखा में एक नया रेस्तरां और पर्यटन विश्रामगृह पूरे किए जा चुके हैं और ये पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं । पानी– पत में एक पैट्रोल पम्प, रोहतक. में झील, रेस्तरां, पैट्रोल पम्प इत्यादि, होडल में जुड़वां कुटीर तथा यादवेन्द्र उद्यान पिंजौर में एक जापानी प्रकार का उद्यान शीघ्र ही बन रहे हैं ।

पांचवीं योजना के वर्ष अर्थात् 1976– 77 के लिए सरकार द्वारा 55 लाख रुपए का अनन्तिम पीव्यय निश्चित किया गया है । चल रहे निर्माण–कार्यों को पूरा करने के साथ–साथ हिसार के निकट सातरौड तथा भिवानी, लोहारू और किला सिरसा में ओटू नामक स्थानों पर नए केन्द्र. स्थापित किए जाएंगे ।

राज्य में शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए साधन जुटाने के विचार से विभाग खान–पान तथा होटल प्रबन्ध के प्रशिक्षणार्थ पानीपत में एक केटरिंग संस्थान भी चला रहा है । इससे राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार का एक नया मार्ग खुलेगा ।

स्वास्थय

राज्य में जनता को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाए प्रदान करने के लिए प्रबल प्रयत्न किए जा रहे हैं । चिकित्सा संस्थाओं की संख्या 1 जनवरी, 1969 को 275 से बढ़कर 1 जनवरी, 1974 तक

334 हो गई है । इन संस्थाओं में बिस्तरों की संख्या भी 1 जनवरी, 1969 को 5,188 थी जो बढ़कर 1 जनवरी, 1974 को 7,345 हो गई ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार पर विशेष बल दिया गया है । पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए नियत 13. 47 करोड़ रुपए के परिव्यय के मुकाबले में योजना के पहले दो वर्षों के दौरान 4. 41 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है । वर्ष 1976–7 7 के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु 2.11 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

वर्ष 1976– 77 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप–केन्द्रों के अतिरिक्त औषधियां सप्लाई करने हेतु 20.86 लाख रुपए खर्च किए जाने प्रस्तावित हैं, इस प्रकार प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की औषधियां प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तथा 2,000 रुपए की औषधियां प्रत्येक उप–केन्द्र में सप्लाई किए जाने का स्तर बना रहेगा, यह स्तर न्यूनतम–आवश्यकता–कार्यक्रम के अनुसार है । चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक भवन तथा एक परामर्शी हस्पताल के लिए एक नत भवन का निर्माण–कार्य पूरा करने के लिए 50 लाख रुपए की राशि निश्चित की गई हए । तीन और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 15 उप–केन्द्रों सम्बन्धी भवन निर्माण–कार्य आरम्भ करने के लिए 10 लाख रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई हे ।

1976– 77 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत हस्पतालों के निर्माणार्थ 85.10 लाख रुपए तथा नवनिर्मित हस्पतालों में नए नार्म के अनुसार अमले की व्यवस्था करने हेतु 6 लाख रुपए की राशि निश्चित की गई है । 10 लाख रुपए के उपकरण खरीदे जाने का प्रस्ताव भी है ।

वर्ष 1976– 77 के दौरान 3.90 लाख रुपए की लागत से दस नए एलोपैथिक औषधालय खोले जाने का प्रस्ताव है । 3. 98 लाख रुपए के व्यय से तेतीस उप–केन्द्र स्थापित किए जाने भी प्रस्तावित हैं । औषधालय के प्रान्तीयकरण की स्कीम पर 0.70 लाख रुपए का व्यय होगा ।

नवनिर्मित चारों जिलों में सें एक जिला पहले से ही राष्ट्रीय जिला टी० बी ० नियन्त्रण कार्यक्म के अन्तर्गत आ चु का है । वर्ष 1978–77 के दौरान एक और जिले को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ले लिया जाने का प्रस्ताव है । इस पर 4 लाख रुपए व्यय होगा ।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों को भी इस बात पर गर्व है कि हरियाणा वर्ष 1974–75 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए देश भर में अग्रगामी राज्य रहा है (तालियां) । हरियाणा राज्य को देश भर में सर्व मुखी समूचे रूप में इस कार्य में प्रथम स्थान मिला है । अब तक 16. 2 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत के मुकाबले में 28.4 प्रतिशत पाल दम्पत्तियों ने परिवार

नियोजन को जीवन के आवश्यक अंग के रूर में स्वीकार कर लिया है । इस कार्यक्रम को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने में पहल की है । इसी तरह कई प्रकार के डिसइन्सैंटिव (Disincentive) लागू करने आर्थात् विभिन्न ऋण, पेशगिया तथाचिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति न देने और जो व्यक्ति दो बच्चों के पश्चात' आगामी– 12 मास के अन्दर अन्दर अपना बन्ध्यकरण नहीं करवाते उन्हें स्थानान्तरण के समय सीमित याव भत्ता देने आदि का निर्णय लेकर पहल की है । इसके अतिरिक्त नए भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों को, यदि उनके दो से अधिक बच्चे हैं सरकारी सेवा जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी । सरकार ने परिवार नियोजन कार्य में प्रथम स्थान पाने वाले सर्वोत्तम जिलों, पंचायतों और औद्योगिक संगठनों के लिए सामूहिक पुरस्कार भी रखे हैं ।

खाद्य पदार्थों में मिलावट की प्रवृत्ति को रोकने के अभिप्राय से इस अभिशाप के विरुद्ध जोरदार अभियान चलाया गया । चलदस्तों और खाद्य–निरीक्षकों की नियुक्ति द्वारा राज्य स्तर से तहसील स्तर तक प्रशासनिक कार्यविधि में सुधार लाया गया । 1, जून 1975 से 31 अगस्त, 1975 तक 1,747 खाद्य–नमूनों का विश्लेषण किया गया, जो कि गत वर्ष कई तदनुरूपी अवधि में विश्लेषण किए गए नमूनो की संख्या से लगभग दुगुनी है । इस अवधि में मिलावट–विरोधी उपायों के कारण मिलावट की

प्रतिशतता घटकर 21.2 हो गई है जो कि पिछले वर्ष– इसी अवधि में 30.7 थी ।

इस अवधि के दौरान, राज्य में नकली तथा निम्न स्तर की औषधियों के नियन्त्रण हेतु ऐसे ही अनेक प्रयत्न किए गए Drugks and Coksmeticks Act 1940 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंधन के कारण औषध बनाने वाली नौ संस्थाओं के लाइसेंसों को रद्द और 6 फर्मों के लाइसेंसों को निलम्बित किया गया । जुलाई, 1975 से अगस्त, 1975 तक गत वर्ष की तदनुरुपी अवधि की अपेक्षा 196 अधिक नमूने (जीव विज्ञान तथा जीव विज्ञान भिन्न) प्राप्त हए ।

चिकित्सा शिक्षा

पांचवीं योजना अवधि के दौरान मैडिकल कालेज, रोहतक को पर्याप्त धन–राशि प्रदान की जाएगी । पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल में ''चिकित्सा शिक्षा'' शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम रूप से 455 करोड़ रुपए की राशि नियत की गई है । वर्ष 1974–75 के दौरान वास्तविक खर्च 78.06 लाख रुपए था और 1975– 76 के दौरान 1.07 करोड़ रुपए खर्च होने की सम्भावना हए । वर्ष 1975–76 के लिए अनन्तिम रूप से एक करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है ।

इस संस्था में बिस्तरों की संख्या 1,056 है और इसमें निम्नलिखित नई स्पैशिलिटिज (Specialities) की वृद्धि की गई है :–

1. बाल रोग शल्य चिकित्सा (Paediatric)

2. प्लास्टिक शल्य चिकित्सा (Plastic Surgery)

3. हृदय विज्ञान (Cardiology)

4. हृदय शल्य चिकित्सा (Cardiac Surgery)

5. तन्विका विज्ञान (न्यूरोलोजी) (Neurology)

6. वृक्क रचना शास्त (Nephrology)

7. यूरोलोजी (Urology)

8. कास्टेरोएन्ट्रोलौजी (Casteroentrology)

9.. तन्विका शल्य चिकित्सा (Neuro-Surgery)

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्तरों पर गुण तथा माला की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है । चौथी योजना अवधि के दौरान 800 नए प्राइमरी स्कूल खोले गए, 279 प्राइमरी स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें मिडल स्कूल और 277 मिडल स्कूलों को हाई स्कूल बना दिया गया, जबकि इनके लक्ष्य क्रमशरू 250, 150 और 60 थे

। वर्ष 1968–69 में पहली से पांचवीं कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 8. 52 लाख थी, छठी से आठवीं कक्षाओं की संख्या 3.08 लाख थी और नौवीं से 11वीं कक्षाओं की संख्या 1.11 लाख थी । वर्ष 1973– 74 में चौथी योजना के अन्त तक यह संख्या बढ़कर क्रमशरू 10.38 लाख, 3.68 लाख तथा 2.04 लाख हो गई । इस संख्या की प्रतिशतता कुल आबादी के विभिन्न आयु वर्गों के लिए क्रमशः इस प्रकार थीः 6–11 वर्ष के आयुवर्ग के लिए 68.1 प्रतिशत, 11– 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 45.8 प्रतिशत, 14–17 वर्ष के आयुवर्ग के लिए 28.7 प्रतिशत । विद्यार्थियों की बढ़ रही संख्या को ध्यान में रखते हुए 8,408 अध्यापकों की नियुक्ति के लक्ष्य के मुकाबले में 13,874 अध्यापकों को नियुक्त किया गया । स्कूल तथा कालेज स्तर पर गरीब और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए 2,320 नई छात्र– वृत्तियां प्रचलित की गयीं । 1974– 75 के दौरान स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 16.19 लाख हो गई और कुल आबादी के मुकाबले में 6–11 वर्ष के आयु वर्ग में प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों की प्रतिशतता पूर्व वर्ष की 68.1 प्रतिशत से बढ़कर 69.1 प्रतिशत हो गई ।

'सामान्य शिक्षा'' शीर्ष के अन्तर्गत पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अन्तिम रूप से 20 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है । चूंकि गत योजना–अवधि के दौरान परिमाण की दृष्टि से पर्याप्त प्रगति हो चुकी थी, अब हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना है । इस बात के दृष्टिगत,

शिक्षण के आधुनिक तरीकों से अवगत कराने के लिए प्राथमिक स्कूलों के 30,000 अध्यापकों को और माध्यमिक स्कूलों के 6,000 अध्यापकों को सेवा–अवधि में प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है । इस योजना पर 67. 50 लाख रुपए की राशि खर्च होगी । योजना के पहले दो वर्षों में 11,000 प्राथमिक अध्यापकों और 2,800 माध्यमिक अध्यापकों को ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है । वर्ष 1976– 77 के दौरान 3,000 प्राथमिक और 1,200 माध्यमिक अध्यापकों को यह प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है ।

विज्ञान की शिक्षा में प्रारम्भिक स्तर पर सुधार लाने के लिए चालू योजना में 20 लाख रुपए की राशि का उपबन्ध किया गया है । योजना के पहले दो वर्षों के दौरान, U.NI.C.E.F. कार्यक्रम के अन्तर्गत 2,512 साईंस किट खरीदने के लिए और इतने ही विज्ञान–अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए 6.73 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है । वर्ष 1978– 77 में 900 किट खरीदने का प्रस्ताव है । स्कूलो में कार्य अनुभव प्रचालन के लिए 5 लाख रुपए की राशि का उपबन्ध किया गया है । इससे विद्यार्थियों में शारीरिक श्रम की आदत पड़ेगी और वे श्रम के गौरव को अनुभव करेंगे । अब तक इस स्कीम के अन्तर्गत 252 स्कूलों को लिया गया है और वर्ष 1976– 77 के दौरान यह स्कीम जारी रहेगी ।

रोहतक में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक अधिनियम पारित किया गया है । हुस उद्देश्य हेतु प्रादेशिक

रीजनल केन्द्र, रोहतक के दर्जे को बढ़ाया जायगा । यह विश्वविद्यालय एकात्मक प्रकृति का होगा और इसमें वातावरण विज्ञानों और अन्तर्विषय अध्यापन पर बल दिया जाएगा । वर्ष 1976–77 के दौरान विश्वविद्यालय के लिए एक करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रस्ताव है । कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बढ़ रही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे चालू वर्ष के दौरान 1. 42 करोड़ रु पए का अनुदान दिया जाना है और आगामी वर्ष के लिए 1.01 करोड़ रुपए का अनुदान देना प्रस्तावित है ।

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार ने राज्य में कालेजों और विश्वविद्यालयों में अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान देने का निर्णय लिया है । (तालियां)

विभिन्न कालेजों से सम्बद्ध एनएसएस. यूनिटों ने ''गन्दगी रोग विरुद्ध युवक'' अभियान के अन्तर्गत 51 कैम्प लगाए, जिसमें सामाजिक चिकित्सा परिवेश सफाई कार्यकम और गांवों में निरक्षरता को दूर करने के कार्य में 2, 500 विद्यार्थियों ने भाग लिया ।

राजकीय कन्या हायर सैकेण्डरी स्कूल, नारनौल के पुराने भवन के गिर जाने तथा असुरक्षित हो जाने के फलस्वरूप एक नए भवन का निर्माण–कार्य जारी है, जो 1976–77 में पूरा हो जाएगा ।

जल सप्लाई

चौथी योजना के अन्त तक कमी वाले क्षेत्रों के 696 गांवों सहित 713 गांवों में जल सप्लाई की सुविधाए जुटाई जा चुकी थीं । 1974– 75 में 76 गांवों को जल सप्लाई की गई थी और 1975–76 में 50 और गांवों में जल सप्लाई की जाने की सम्भावना है । 1976–77 के दौरान जल सप्लाई के लिए 2.81 करोड़ रुपए की राशि का उप– बन्ध करने का प्रस्ताव है जिसमें से 1.36 करोड़ रुपए कमी वाले क्षेत्रों के 65 गांवों में ग्रामीण जल सप्लाई के लिए निर्धारित किए गए हैं । प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक क्रियान्वित करने के सरकार के संकल्प को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1976–77 में ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों के लिए उपबन्ध को बढ़ा दिया गया है ।

अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण

सरकार अनसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और विमुक्त जातियों के उत्थान को उच्च प्राथमिकता देती है । उनके आर्थिक उत्थान, शैक्षणिक उन्नति और उत्तम सामाजिक स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा राज्य में हरिजन विधवाओं को सिलाई प्रशिक्षण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था/स्कूलों में प्रशिक्षण वजीफे, सूअरों की खरीद के लिए अनुदान, शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां, मकानों/चौपालों के निर्माण तथा आर्थिक सहायता जैसी अनेक स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

वर्ष 1978– 77 अर्थात् पांचवीं योजना के तीसरें वर्ष के दौरान योजना पक्ष में 24. 20 लाख रुपए का उपबन्ध किया गया है । उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु आवास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । वर्ष 1976–77 के दौरान मकानों के निर्माण के लिए 7 लाख रुपए का उपबन्ध कियां गया है । उत्पीड़ितों के सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए चौपालों के निर्माणार्थ 5 लाख रुपए का उपबन्ध किया गया है । इसके अतिरिक्त, हरिजन विधवाओं को आत्म–निर्भर बनाने के लिए पांचवीं योजना में 'हरिजन विधवाओं को सिलाई प्रशिक्षण' नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है, जिसके अन्तर्गत इस विभाग द्वारा चलाए जा रहे सभी समीपस्थ सामुदायिक केन्द्रों में प्रशिक्षण पाने वाले प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 20 रुपए प्रति मास दिए जाएंगे । प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समाप्त किए जाने के पश्चात् प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को एक–एक सिलाई मशीन दी जाती है ।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हरिजन उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने हेतु योजनेत्तर स्तर पर हरिजन लड़के तथा लड़कियों को प्रशिक्षण देने के निमित्त 180 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता वाले अम्बाला, रोहतक और भिवानी में तीन पूर्व–परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं । सरकार के प्रयत्नों को और आगे बढ़ाने के लिए 2 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी से हरियाणा हरिजन कल्याण निगम प्राइवेट लिमिटिड, जनवरी, 1971

से कार्य कर रहा है । निगम ने 30–10–75 तक विन्भिन स्कीमों/व्यापारों, जैसे डेरी फार्मिंग, ट्रैक्टरों, टैम्पुओं और टैक्सियों की खरीद और चमडे के कार्य इत्यादि के लिए लगभग 91.32 लाख रुपए का कर्ज स्वीकृत किया है । हरियाणा हरिजन कल्याण निगम द्वारा 1,786 लाभ–ग्राहियों को 56. 83 लाख रुपए की राशि पहले ही वितरित की जा चुकी है । निगम द्वारा करनाल में एक जूता उत्पादन केन्द्र स्थापित किया जा चुका है और इसी प्रकार के रोजगार जुटाने वाले औद्योगिक यूनिट सोनीपत मैं स्थापित किए जा रहे हैं, 'जोकि राज्य के अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए अधिक रोजगार सुनिश्चित करेंगे । योजनेत्तर स्तर पर वर्ष 1976– 77 के दौरान निगम को 25 लाख रुपए की राशि देने का उपबन्ध किया गया है, जिसमें से 10 लाख रुपए कर्ज के रूप में और 15 लाख रुपए हिस्सा पूंजी के अंशदान के रूप में होंगे ।

आजीविका के साधनहीन वृद्ध और निराश्रित व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए वर्ष 1969 में वृद्धावस्था पैंशन स्कीम दोबारा शुरू की गई थी । इस स्कीम के अन्तर्गत 6858 व्यक्ति 25 रुपए प्रति मास प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैंशन ले रहे हैं । आगामी वित्त वर्ष में इस स्कीम के अन्तर्गत 7,000 व्यक्तियों को 19 लाख रुपए देने का उपबन्ध किया गया है । (तालियां)

बजट घाटा

अब मैं एक बार फिर आपका ध्यान बजट दस्तावेजों से इंगित राज्य की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । वर्ष 1978– 77 के अन्त में राज्य के बजट में 18.30 करोड़ रुपए का घाटा होगा, जिसमें इस वर्ष का 8.92 करोड़ रुपए का अनुमानित घाटा भी शामिल है । आशा है कि हम चालू वर्ष का 8.92 करोड़ रुपए का अनुमानित घाटा कम कर सकेंगे । राज्य सरकार ने कराधान प्रशासन की कार्यप्रणाली में पर्याप्त सुधार इस उद्देश्य से किया है कि उन खराबियों को दूर किया जा सके, जिनके कारण टैक्सों की चोरी आसान थी और टैक्स की वसूली समय पर तथा तेजी से की जा सके । राज्य सरकार योजनेत्तर खर्च पर कड़ी नजर रखती रहेगी ताकि अनावश्यक और फिजूल खर्च को रोका जा सके । इसके अतिरिक्त हमें भारतीय खाद्य निगम को बेचे गए खाद्यान्नों की बिक्री के फलस्वरूप अतिरिक्त प्राप्तियों की आशा है । क्योंकि इन सभी उपायों की सफलता के बारे में इस समय ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, अतरू बजट अनुमानों में इन प्राप्तियों को अन्कित नहीं किया गया है । फिर भी 1976–77 का घाटा, जिसका अनुमान 16.30 करोड़ रुपए है, इन उपायों के सफल होने पर कम हो जाएगा ।

सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति सदा जागरूक रही है और समय– समय पर इस सम्बन्ध में अतिरिक्त भत्ते तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करती रही हैं । जैसे कि मैंने पहले कहा है अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की 3 किश्तें अभी हाल ही में स्वीकृ

त की गई हैं । राज्य सरकार ने अपने सीमित साधनों के बावजूद अपने कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के फलस्वरुप पहली मार्च 1976 से मंहगाई भले की 2 अतिरिक्त किश्तें देने का निर्णय लिया है (तालियां) । ऐसा करने से राज्य कोष पर 3. 18 करोड़ रुपए का अधिक भार पड़ने की सम्भावना है । वर्ष 1976—7 7 का घाटा, इस कारण से उतना ही बढ़ जाएगा । फिर भी मैं सम्मानीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि इतने घाटे के होते हुए भी राज्य सरकार के विकास कार्यों की गति में कमी नहीं आने दी जाएगी (तालियां) और इनको जारी रखने के अतिरिक्त इनको पूरा करने में तेजी भी लाई जाएगी । हमें आशा है कि भारत सरकार हमें वर्ष 197 6— 77 में प्राथमिक क्षेत्रों की स्कीमों के लिए अधिक माली सहायता देगी, जिससे उक्त अनुमानित घाटा काफी कम होने की आशा है । राज्य सरकार के खर्चे पर यथासम्भव नियन्त्रण रखा जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो हो सकता है कि नए कराधान उपायों के बारे में भी सरकार क सोचविचार करना पड़े ।

अब मैं आपका ध्यान संस्थागत वित्त की ओर आकर्षित करता हूं जो राज्य के विकास कार्यों में धन जुटाने में सहायक हो सकता है और इस प्रकार राज्य के साधनों पर दबाव को कम कर सकता है । व्यापारिक बैंकों ने कृषि ऋण देने के सम्बन्ध में अच्छी भूमिका निभाई है । कुछ वर्ष पहले सामाजिक नियन्त्रण के चरण के समय व्यापारिक बैंकों का सहयोग कुछ कुछ ही आरम्भ हुआ

था । परन्तु अब बड़े बैकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इनके सहयोग में वृद्धि हुई है । यह जरूरी है कि व्यापारिक बैकों की शाखाओं को ग्रामीण क्षेत्रो में ऋण वितरण हेतु स्थापित किया जाए । परन्तु यह अनुभव किया जा रहा है कि ग्रामीण शाखाएं अब भी ऋण वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करने की बजाय अधिकतर जमाकेन्द्र के रूप में ही चल रही हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि बैंक ग्रामीण परिस्थितियों से बहुत परिचित नहीं हैं । वास्तव में इस कारण से ही राज्य प्रयोजक ग्रामीण बैंकों की स्थापना का विचार उत्पन्न हुआ है । सम्माननीय सदस्य यह जानते हैं कि हरियाणा उन राज्यों में से एक है, जिनमें कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना पहले पहल हुई थी । ऐसा एक बैक भिवानी में अक्तूबर, 1975 से चल रहा है । ऐसा ही एक और बैक गुडगावां में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है । इन ग्रामीण बैकों की इक्विटी (Equity) में भारत सरकार, राज्य सरकार तथा प्रायोजिक बैंक का भाग होता है । ये ग्रामीण बैक सहकारी और व्यापारिक बैंक आदि संस्थाओं के अतिरिक्त विभिन्न विकास कार्यों के लिए लोगों को कुण प्रदान करेंगे ।

मेरे लिए सम्माननीय सदस्यों के ध्यान में यह लाना हर्ष की बात है कि जहाँ तक जमा तथा वितरण के अनुपात तथा फैलाव का सम्बन्ध है राज्य की स्थिति अखिल भारतीय औसत के मुकाबले में बहुत अच्छी है (तालियां) । हरियाणा में जमा तथा वितरण का अनुपात 70 प्रतिशत है । अब हम बाकी 30 प्रतिशत

जमाराशि कोभी कृषि, उद्योग तथा बेरोजगार लोगों को माली सहायता देने हेतु प्रयोग में लाने में प्रयत्नशील हैं ।

आभार प्रर्दशन

अब मैं बजट तैयार करने में वित्त विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किए गए परिश्रम के लिए उनका आभार प्रकट करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं । उनके इस परिश्रम के बिना मेरे लिए बजट को सदन के सम्मुख निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत 'करना सम्भव न था । महालेखाकार तथा उनके अगले द्वारा दी गई सहायता के लिए भी मैं उनका आभारी हूं । मैं बजट दस्तावेजों को मुद्रित करने में चण्डीगढ प्रशासन द्वारा दिए गए सहयोग के लिए भी आभारी हूं ।

महोदय, अब मैं वर्ष, 1976– 77 के अनुमानों को प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हू ।

जयहिन्द ।

(तालियां)

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 2.00 p.m. on Monday, the 19th January, 1976.

12.06 बजे

(The Sabha then adjourned till 2.00 p.m. on

Monday. the 19th January, 1976).